लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 26–शनिवार, 14 दिसम्बर, 1968/23 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 26—Saturday, December 14, 1968/Agrahayana 23, 1890 (Saka)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	Committee on Subordinate Legislation ...	1
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	Second and Third Reports ..	1
नियम 377 के अन्तर्गत विदेशी पूंजी विनियोजन तथा सहयोग के बारे में सदस्य द्वारा उठाए गए विषय पर मंत्री का वक्तव्य	Statement by minister regarding foreign capital Investment and Collabration raised by member under rule 377	1-3
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ...	1
सभा का कार्य	Business of the House	3-4
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	4-6
हरियाणा विधान सभा के जाटूसाना निर्वाचन क्षेत्र में उप–चुनाव	Haryana Bye-Election in Jatusana Constitution	4
न्यायालय अवमान विधेयक	Contempt of Courts Bill	6
राज सभा की विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider Rajya Sabha recommendation to Joint Committee	6
श्री के. एस. रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	6
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे),	Supplementary Demands for Grants (Railways),	7
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	7
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	9
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	10
श्री जे. मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	10
श्री बसुमतारी	Shri Bisumatari	11

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री लोबो प्रभू	Shri Lobo Prabhu	12
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	13
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	13
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	14
श्री चं. चु. देसाई	Shri C. C. Desai	15
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	15
श्री कं. हाल्दर	Shri K. Haldar	16
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	17
श्री पी. विश्वम्भरन	Shri P. Voswambharan	17
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	18
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	18
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchaudhuri	19
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	19
छात्रों में असंतोष के बारे में चर्चा	Discussion re. student unerest	20
श्री रा. की. अमीन	Shri R. K. Amin	20
श्री बेदव्रता बरुआ	Shri Bedabrata Barua	22
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	23
श्री अ. सि. सहगल	Shri A. S. Saigal	26
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	27
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	28
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	28
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	29
श्री ए. श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	29
श्री सीताराम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	31
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	31
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen . ..	32
उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के बारे में चर्चा	Discussion re. demands of teachers of Higher Secondary Schools in U.P.	33
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	33
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain ...	35
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया	Shri D.N. Patodia	35
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ...	36
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu –	36
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ...	37
श्री नारायण स्वरूप शर्मा	Shri Narain Swarup Sharma ...	38
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav ...	39
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	40
श्री रामसेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav –	40
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy ... –	41
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shrs Tenneti Viswanatham	41
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh ...	42
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	42
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	42
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad – ...	42

लोक-सभा
LOK-SABHA

शनिवार, 14 दिसम्बर 1968/ 23 अग्रहायण, 1890 (शक)
Saturday, December 14, 1968/Agrahayana 23, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
(COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION)

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री मि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी-समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन प्रतिवेदनों को संसदीय पत्रों के साथ परिचालिक किया जायेगा। इस बात पर विचार किया जायेगा कि इन पर चर्चा की जाये या नहीं।

———

नियम 377 के अन्तर्गत विदेशी पूंजी विनियोजन तथा सहयोग के बारे में सदस्य द्वारा उठाये गये विषय पर मंत्री का वक्तव्य
STATEMENT BY MINISTER REGARDING FOREIGN CAPITAL INVESTMENT AND COLLABRATION RAISED BY MEMBER UNDER RULE 377

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : चूंकि कल मैं राज्य सभा में था, अतः श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। एक बार यह सोचा गया था कि दिवंगत प्रधान मंत्री द्वारा 1949 में घोषित की गई नीति में

पुनरीक्षण करना आवश्यक है अथवा नहीं। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि उस नीति का पुनरीक्षण अथवा उसमें संशोधन करना आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ विदेशी सहयोग के बारे में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटारे के बारे में प्रक्रिया का निर्णय किया गया था। 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के सम्बन्ध में मैंने उल्लेख किया था कि विदेशी सहयोग की नीति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु सरकार ने विदेशी विनियोजन निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है। सरकार ने विदेशी सहयोग और पूंजी विनियोजन की प्रक्रिया के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के बारे में भी निर्णय किया है। 27 अगस्त, 1968 को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि सरकार का विचार उद्योगों को दो सूचियों में विभाजित करने का है। एक वे उद्योग जिनके लिए सहयोग की आवश्यकता नहीं और दूसरे वे जिनमें वर्ष में एक बार विदेशी सहयोग की आवश्यकता है। नीति के बारे में कोई नया वक्तव्य नहीं दिया गया। विभिन्न स्तरों पर भी जब कमी कार्यवाही की गई है, तो सभा को सूचित किया गया है। अतः इस प्रकार के आरोप लगाने पर, कि मैंने सब का विश्वास प्राप्त किये बिना पहले ही सभा से बाहर कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया हैं, आश्चर्यजनक है। इस निकाय के अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। यह अधिकारों का प्रत्यायोजन कार्यकारी आदेशों के अनुसार किया गया था और जिसके बारे में सभा को सूचित कर दिया गया था। इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आइसक्रीम, ब्रेसरी और बिस्कुट आदि के बारे में सहयोग प्राप्त करने का भी प्रश्न उठाया गया था। यह सच है कि पहले कुछ मामले, जैसे बिस्कुट आदि में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई थी। परन्तु भविष्य में यदि किसी ऐसे उद्योग के लिये विदेशी सहयोग का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसे विषय सूची में शामिल नहीं किया गया, तो उस पर सब बातों को और उस उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

हम उन उद्योगों के लिये इसकी अनुमति नहीं देंगे, जिनके बारे में जानकारी देश में ही उपलब्ध है।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या सरकार अनावश्यक विदेशी सहयोग के परिणाम-स्वरूप बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा को रोकने का आश्वासन देगी। विदेशी सहयोग की उन्हीं मामलों में अनुमति दी जायेगी, जिन मामलों में विदेशी सहयोग राष्ट्रीय हित में आवश्यक होगा।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार विदेशी विनियोजन बोर्ड की एक उप-समिति नियुक्त करने के बारे में सहमत हो गई है और यह उप-समिति अन्य औद्योगिक विकास तथा समवाय, वित्त और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करने के अतिरिक्त अन्य मामले जिनमें 25 प्रतिशत विदेशी सहयोग और एक करोड़ रुपये से अधिक धन का विनियोजन नहीं होगा, के बारे में भी विचार करेगी।

यह स्पष्टतया नई नीति है। केवल यह कहने मात्र से, कि विदेशी विनियोजन बोर्ड की स्थापना की गई है, माननीय मंत्री अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। अतः सभा का अपमान किया गया है। अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों पर भी विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभा को इस बात का आभास न हो, कि उससे इस मामले से अनभिज्ञ रखा गया है या सभा में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 16 दिसम्बर, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा का कार्य निम्नलिखित होगा :—

(1) आवश्यक सेवायें बनाए रखने के विधेयक, 1968 का अननुमोदन करने वाले संकल्प पर आगे विचार और आवश्यक सेवायें बनाए रखने के विधेयक 1968 पर आगे विचार और उसे पास करना।

(2) नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक, 1968 (विचार तथा पास करना)

(3) बिहार में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के संकल्प पर चर्चा।

(4) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1968 (विचार तथा पास करना)

(5) संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक 1968 को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।

(6) सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक 1968 (विचार तथा पास करना)

(7) जन्म तथा मृत्यु पंजीयन विधेयक 1968 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में (आगे विचार तथा पास करना)

(8) राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पास करना में (क) अधिवकता (दूसरा संशोधन) विधेयक 1968
(ख) प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1967

(9) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर आगे चर्चा। मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1968 को 6 बजे सांय

(10) असैनिक सुरक्षा नियमों 1968 में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा बुधवार, 18 दिसम्बर को साँय 6 बजे।

(11) चुनाव संचालन (दूसरा संशोधन) नियमों, 1968 को रद्द करने के सम्बन्ध में श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा बृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर को सांय 5 बजे।

(12) श्री ए० के० सरकार जांच समिति (इस्पात के सौदे) के प्रतिवेदन के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा, जो सर्व श्री मधुलिमये और जार्ज फरनेन्डीज द्वारा उठायी जायेगी। बृहस्तपतिवार, 19 दिसम्बर, सांय 6 बजे।

सत्रावधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

हरियाणा विधान सभा के जाईसाना निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव :

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : There should be fair and impartial elections in the country. But it is observed from the incidents in Jatusana Constituency that there is mockery of democracy. The police in plain clothes have been arresting thousands of people there and torturing them. We have come to know that the people are being intimidated. It has been published in the Indian Express that the opposition leaders have complained to the Chief Election Commissioner to the effect that Government is using its official machinery to further the prospects of the congress candidate at the polls.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अनुसार माननीय सदस्य आप की अनुमति से वह मामला उठा सकते हैं, जो केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में आता हो। राज्य के सरकारी तन्त्र के दुरुपयोग का प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : निर्वाचन आयोग संघीय विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें संघीय विषय से सम्बन्धित मामला उठाने की अनुमति दी है। इस मामले की सूचना निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले का निर्वाचन आयोग के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका आरोप यह है कि सरकारी तन्त्र का, जिस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण है, दल के हित के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आरोप हरियाणा सरकार के विरुद्ध है। हरियाणा का अपना विधानमंडल कार्य कर रहा है और वहां पर एक उत्तरदायी सरकार विद्यमान है। अतः उस सरकार के आचरण का मामला यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

निर्वाचन आयोग के बारे में हम आपकी अनुमति से चर्चा कर सकते हैं। परन्तु यह मामला राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के विरुद्ध यहां पर कोई मामला उठाना राज्य विधानमंडल के अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को यह बात कह दी थी। उन्हें केवल निर्वाचन आयोग को सतर्क करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इस बात से सहमत हूँ।

श्री उमानाथ (पुट्टकोटै) : आरोप यह है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह एक केन्द्रीय विषय है। उनका कथन यह है कि राज्य सरकार के अधिकारी, जो अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग की ओर से कार्य कर रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इसकी ओर निर्वाचन आयोग का ध्यान आकर्षित करना था, परन्तु उन्होंने अन्य कई बातें कहनी आरम्भ कर दी हैं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The point is that there may not be impartial election in the violations of the provision of an Act which falls under the category of Central subjects. Unless this position is explained, Election Commissioner cannot be alerted.

उपाध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग को सतर्क करने के लिए उन्हें अनुमति दी गयी थी।

श्री स० मो० बनर्जी : एक उपचुनाव में, जिसमें श्री बलराज मधोक निर्वाचित हुए थे, श्री नवनीत राम भाटिया को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि वह श्री ओम् प्रकाश गुप्ता (उम्मीदवार) को वोट देने के लिये लोगों से कह रहा था। श्री अनन्ताश्यानम आयंगर ने इस मामले को उठाने की अनुमति दी थी। अन्तर केवल इतना है कि दिल्ली में कोई विधान मंडल नहीं था जबकि हरियाणा में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी बड़ा अन्तर है। फिर दिल्ली केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र में है। इस बात का इस मामले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मंत्री महोदय का विचार बिल्कुल ठीक है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : विरोधी पक्ष का आरोप यह है कि सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस का उपयोग कर रही है। सरकार ने दूर-दूर के गावों में इसलिये पुलिस भेजी है ताकि वहां के लोग स्वेच्छा से मतदान कर सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta : The leaders of Vishal Haryana Party have complained to the Chief Election Commissioner that Government is using official machinery to further

the prospects of the Congress at the Poll. I request the Law Minister to send an officer there just to see that free and fair election is conducted. I wantan assurance from the Law Minister to this effect. Moreover intimadation of people should also be stopped.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रचार करने के ढंग से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि विधि मंत्री माननीय सदस्य के विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : संविधान के अनुसार राज्य सभा के लिए चुनाव करवाना भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम है। अतः यदि हरियाणा में चुनाव के बारे में कोई शिकायतें हैं तो मैं इन सभी वक्तव्यों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेज दूंगा। वह एक निष्पक्ष अधिकार है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह निष्पक्ष निर्वाचन का आश्वासन दें।

न्यायालय अवमान विधेयक
(CONTEMPT OF COURTS BILL)

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 29 नवम्बर, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कतिपय न्यायालयों की न्यायालय के अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति को परिभाषित और परिसीमित करने के लिए और उनकी तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित तीस सदस्य नामनिर्देशित किये जायें, अर्थात् :—

श्री नाथूराम अहिरवार, श्री स० मो० बनर्जी, श्री रा० ढो० भण्डारे, श्री यशवन्त राव चव्हाण, श्री चित्तीबाबू, श्री राम धनी दास, श्री देवीकन, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री कंवर लाल गुप्त, श्री जो० ना० हजारिका, श्री गयूर अली खां, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री महाराज सिंह, श्री बि० प्र० मण्डल, श्री गोविन्द मेनन, श्री विश्वनाथ मेनन, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री पीलू मोदी, श्री आ० ना० मूल्ला, श्री सी० मुत्तुसामी, श्री अमृत नाहाटा, श्री क० क० नायर, श्री भालजीभाई परमार, चौधरी रणधीर सिंह, श्री क० नारायण राव, डा० शि० कु० साहा, श्रीमति सावित्री श्याम्, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री सिद्ध्या, श्री प्र० न० सोलंकी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1968 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 29 नवम्बर, 1968 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश

से सहमत है कि यह सभा कतिपय न्यायालयों की न्यायालय के अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति को परिभाषित और परिसीमित करने के लिए और उनकी तत्सम्बन्धी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनो सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा में निम्नलिखित तीस सदस्य नामनिर्देशित किये जायें, अर्थात् :-

श्री नाथू राम अहिरवार, श्री स० मो० बनर्जी, श्री रा० ढो० मण्डारे, श्री यशवन्त राव चव्हाण, श्री चित्तीबाबू, श्री राम धनी दास, श्री दीवीकन, श्री श्रीचन्द गोयल, श्री कंवर लाल गुप्त, श्री जो० ना० हजारिका, श्री गयूर अली खां, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री महाराज सिंह, श्री बि०प्र० मण्डल, श्री गोविन्द मेनन, श्री विश्वनाथ मेनन, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री पीलू मोदी, श्री आ०ना० मुल्ला, श्री सी० मुत्तुसामी, श्री अमृत नाहाटा, श्री कृ०कृ० नायर, श्री भालजीभाई परमार, चौधरी रणधीर सिंह, श्री क० नारायण राव, डा० शि० कु० साहा, श्रीमती सावित्री श्याम, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री सिद्धय्या, श्री प्र० न० सोलंकी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभा का कार्य—जारी
BUSINESS OF THE HOUSE-Contd

Shri Rabi Rai (puri) : I want a clarification about the procedure, Two subjects under Rule 193 have been shown in to-day's oreder paper one is regarding the teachers of Uttar pradesh and the other is regarding students. But it has not been indicated that at what time these will be taken up. I would like that these should be taken at 2, P. M, so that the discussion may be concluded by 6 P. M.

उपाध्यक्ष महोदय : इनमें से प्रत्येक को दो घंटे का समय दिया जायेगा । यदि इसका ठीक तरह पालन किया जाये तो चर्चा अवश्य पूरी हो जायेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : What is the procedure to be followed ? Will both of these be taken up together or will the discussion on Hindu University start first ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन दोनों विषयों पर पृथक-पृथक चर्चा करने की मांग की गई है । अतः इनको चर्चा के लिये पृथक-पृथक ही लिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि यह मध्यान्ह भोजन से पहले पूरी हो जाये ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : ये सभी मांगें नाम मात्र की हैं । ये मांगें नयी सेवाओं तथा नये कार्यों के लिये, जो इस वर्ष बजट प्रस्तुत करने के बाद आरम्भ

की गई है, लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ये मांगें प्रस्तुत की गई है, और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में और अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि सभा ये मांगे स्वीकार कर ले।

वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (रेलवे) प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
2	विविध व्यय	रुपये
14	नई लाइनों का निर्माण-पूंजी और मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	4,000 1,000
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्य-ह्रास, आरक्षित निधि और विकास निधि	3,000

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	11	श्री वेणी-शंकर शर्मा	भागलपुर-मन्दार हिल ब्रांच लाइन को, बरास्ता डुमका, जैसीडीह अथवा देव घर तक बढ़ाने में असफलता।	1,000
	12		भागलपुर-मन्दार हिल ब्रांच लाइन को बंका तक बढ़ाने में असफलता।	
	13		भागलपुर-मन्दार हिल ब्रांच लाइन पर ढाका मोड़ के सामने एक फ्लैग स्टेशन बनाने में असफलता।	
	14		कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे बनाने में असफलता।	
	15	श्री जे० मुहम्मद इमाम	होस्पेट-यशवन्तनगर रेलवे लाइन से सम्बन्ध जोड़ने के लिए चिकजाजपुर-चित्र-दुर्ग रेलवे लाइन का विस्तार करने में असफलता।	

15	18	श्री पी० विश्वम्भरन	त्रिवेन्द्रम से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन बनाने में असफलता ।
	20		एर्णाकुलम्-क्विलोन मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।
14	19	श्री चं० चु० देसाई	गुजरात के सबरकंठ जिले में मोआसा को एक ओर कपड़वंज के साथ और दूसरी ओर टिटोई के साथ मिलाने के लिये रेलवे लाइन बनाने में असफलता । अहमदाबाद से हिम्मतनगर जाने वाली
15	21		मुख्य बड़ी लाइन पर हिम्मत नगर स्टेशन के ठीक बाहर एक ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।
2	22	श्री लोबो प्रभु	आपाती आधार पर सर्वेक्षणों के लिये 13.5 लाख रुपये और 9.5 लाख रुपये के व्यय के लिये सरकार की वचनबद्धता जबकि बहुत से पूरे किये हुए सर्वेक्षणों के संबंध में मंजूरी नहीं दी गई है और दूसरे यह कि ये प्रस्ताव बड़ी लाइन में बदलने अथवा विद्युतीकरण संबंधी सामान्य योजना से संबंधित नहीं है ।
14	23		86 लाख रुपये के व्यय के लिए सरकार की वचनबद्धता, जिसका बजट के समय पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और जिसे अगले बजट के लिए रोका जा सकता था ।
15	28		32 लाख रुपये और 86.26 लाख रुपये के व्यय की दो मदों को और अनुबन्ध में उल्लिखित 10 लाख रुपये से अधिक कीपाँच नई सेवाओं के लिये पुनर्विनियोजन को मूलबजट में शामिल कर लिया जाना चाहिये था ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Mr. Deputy Speaker, my cut motion relates to Bhagalpur-Mandar Hill Branch line only. Banka area of Bihar is a very backward area of the country. Santhal Pargana adjoining it is even more backward area. If Bhagalpur-Mandar Hill Branch line is extended via Dumka, to connect the main line at Deoghar, that region will be able to make its development.

Sahibganj loop line upto Barharwa is almost ready and is proposed to be further extended. I propose that instead of doubling it further, Bhagalpur-Mandar Hill Branch line should be extended, which would serve both the purposes of doubling the line as well as developing that region.

The condition of the only train from Delhi passing through Bihar region namely the Upper India Express is incredibly bad. What to say of third and second class compartments of this train, it has no proper arrangement of lights, fans and water in the first class compartments. The sanitary arrangements in this train are very deplorable. Some thing should be done in this regard.

The incidents of thefts, dacoities etc. have increased in trains passing through Bihar. When the attention of the Government was drawn to this fact, it was said that it was a state subject. In this connection I beg to submit that some thing must be done to stop such incidents. It is said that some branch lines are going to be closed on account of being uneconomic. The fact is that they are running in loss because of the inefficiency and connivance of the railway staff due to which very large number of people travel without tickets. If ticketless travel is stopped, these lines will not be uneconomic any more.

✓**Shri Bishwanath Roy** (Deoria) : Mr. Deputy Speaker, one of the main reasons of decline in the income of the Railways is operational ineffenciency due to which there is a diversion of traffic to the road transport. It is, therefore, essential to improve their operational effeciency to attract more traffic. If efforts are made to bring informity in the metre and broad gauge lines, transport of goods from one place to another it would be quick and easier. The metre gaguge lines should be converted into broad gague lines as far as possible.

The Railway Department should also pay attention to the interests and convenience of the public alongwith increasing the income. Preparations are being made to eject people from seven villages near Bhatni junction in connection with the construction of a line. If a curve is given to the line, those villages will be saved from ejection.

✓**श्री जे० मुहम्मद इमाम** (चित्रदुर्ग) : हालांकि मन्त्री महोदय सांकेतिक उपबन्ध के रूप में 8000 रुपये के अनुपूरक अनुदानों के लिये इस सभा द्वारा अनुमोदन की मांग कर रहे हैं, परन्तु इन तीन नई योजनाओं में से प्रत्येक पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। हम इन योजनाओं का महत्व कम नहीं करते, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि नई योजनाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में रेलवे मन्त्री द्वारा जो आश्वासन दिये गये थे, पहले उनको अमल में लाया जाना चाहिये था और बाद में इन योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिये था।

रेलवे का दावा है कि उसने देश में लगभग 4000 मील लम्बाई में नई लाइनों का निर्माण किया है। इन लाइनों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश लाइनें देश के उत्तरी क्षेत्र में हैं। बहुत कम नई लाइनें दक्षिण में शुरु की गई हैं। विशेष कर मैसूर राज्य की बहुत ज्यादा उपेक्षा की गई है। जब मैसूर रेलवे पर पुरानी सरकार का स्वामित्व था तो उनके पास कुछ योजनाएं थी और धनराशि भी थी। परन्तु जब एकीकरण का प्रश्न उठा और योजना आयोग के तत्कालीन उप प्रधान श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने तत्कालीन मैसूर सरकार से मैसूर रेलवे को मध्य रेलवे के साथ मिलाने के बारे में बातचीत की तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैसूर सरकार द्वारा आरम्भ की गई सभी योजनाओं को पूरा किया जायेगा। ज्यों ही इसे मध्य रेलवे के साथ मिला दिया गया केन्द्रीय सरकार अपने दायित्व से मुकर गई। उसके बाद से मैसूर में एक भी लाइन नहीं बनाई गई है। मंगलोर-हसन लाइन शुरु की गई है परन्तु उसमें बड़ी धीमी गति से प्रगति हो रही है।

नई लाइनें बनाने की बात तो दूर रही। रेलवे मंत्री कहते हैं कि अलाभप्रद रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया जायेगा। मैं मानता हूं कुछ लाइनें अलाभकारी हैं परन्तु उन्हें उखाड़ फेंकने की बजाय कारणों का पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

उदाहरण के लिये चिकजाजुर से चित्रदुर्ग तक एक बीस मील लम्बी लूप लाइन है। इसे बेजवाड़ा-हुबली लाइन तक बढ़ाया जाना था। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने इस तरह का आश्वासन भी दिया था।

होसपेट से यशवन्तनगर तक एक और 20-25 मील लम्बी लूप लाइन है। इन दोनों लाइनों के बीच 50-60 मील की दूरी है। यदि इन दोनों लाइनों को मिला दिया जाये तो यह लाभकारी बन सकती हैं। यह ऐसे क्षेत्र में से होकर गुजरेगी जहां से प्रतिवर्ष 2000 टन से अधिक मैंगनीज अयस्क बाहर भेजा जाता है। इसके अलावा यह दो महत्वपूर्ण लाइनों को मिलाएगी-बंगलौर-पूना और बेजवाड़ा-हुबली लाइन।

ऐसे ही तालगोया लाइन को भटकल तक बढ़ाया जाना था और चामराजनगर लाइन को सत्यामंगल तक बढ़ाया जाना था। इन सब की योजनाएं पुरानी मैसूर सरकार के पास तैयार थीं। केवल रुकावट यह थी कि तत्कालीन कम्पनियों ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। मैसूर रेलवे के विलय के समय इन सब योजनाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अब उसे पूरा नहीं किया जा रहा है।

रेलवे मन्त्री भी मैसूर राज्य के हैं और वे बहुत ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वे मैसूर राज्य का दौरा करें और इन लाइनों के अलाभकर होने के कारणों का पता लगा कर उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मुझे आशा हैं कि भारत सरकार अपने पुराने आश्वासनों को पूरा करेगी।

श्री बसुमतारी (कोकरा झार) : आसाम राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है हालांकि इसके पास पर्याप्त संसाधन हैं। इस क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं न होने के कारण इसका विकास नहीं किया जा सका। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि आपातकाल के समय में वहां पर संचार सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। हमें कलकत्ता से बोंगाइगांव तक बड़ी लाइन दी गई। अब इसे जोगीघोपा तक बढ़ाया गया है। इसे और आगे बढ़ाने का काम तभी चालू हो सकता है जब ब्रह्मपुत्र पर पुल बना दिया जाये। यदि जोगीघोपा के पास ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने के लिये धन राशि नहीं है तो इस लाइन को जोगीघोपा से गोहाटी तक बढ़ाया जाना चाहिये।

कोकराझार स्टेशन को अपग्रेड किया जाना चाहिये। दिल्ली से ही आसाम मेल में एक भोजनयान की व्यवस्था की जानी चाहिये।

यदि उपरोक्त बड़ी लाइन को कटिहार के परे अन्य लाइन से नहीं मिलाया जाता है तो यह लाइन बेकार हो जाती है। इस कलकत्ता बोंगाइगांव बड़ी लाइन और दिल्ली-बारौनी रेलवे लाइन के बीच कोई सम्पर्क नहीं हैं। इन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर मिलाया जाना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : सांकेतिक अनुदानों के माध्यम से यह मंत्रालय ऐसी योजनाओं के लिये वित्तीय मंजूरी ले रहा है जिन पर करोड़ों रूपये खर्च होंगे। यह कहना उचित नहीं है कि एक लाइन पर 1000 रूपये खर्च होंगे या 4000 रूपये खर्च होंगे जबकि एक पर 13 लाख रूपये खर्च होंगे और दूसरी पर 9 लाख रूपये खर्च होंगे। यह अधिक अच्छा होता कि लोक लेखा समिति की इस विशेष टिप्पणी का लाभ नहीं उठाया जाता कि सांकेतिक अनुदान सांकेतिक होने चाहिये।

यह भी अच्छा होगा यदि भविष्य में इस प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये क्योंकि हम इनपर अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकते हैं। इससे यह आभास होता है कि खर्च का पूर्वानुमान ठीक ढंग से नहीं लगाया जाता और उनके पास लगभग एक करोड़ रूपये बकाया हैं जिन्हें वे अपनी मन पसन्द योजनाओं पर खर्च कर सकते हैं। ये प्रस्ताव मुख्य बजट पेश करते समय रखे जाने चाहियें।

1947 से 35 प्रतिशत सर्वेक्षणों की भी स्वीकृति नहीं दी गई है। या उनपर अमल नहीं किया गया है। सर्वेक्षणों पर खर्च की गई भारी रकम स्टेशन बनाने या पटरी को दोहरा करने पर खर्च की जाती तो यह ठीक ढंग से खर्च की गई समझी जाती। परन्तु यह सब कर्मचारियों पर खर्च की जाती है। केवल बी. बी. के. रेलवे पर पिछले तीन वर्षों में 5 सर्वेक्षण किये गये। इनमें से एक पर 15 लाख रूपये खर्च हुए परन्तु अभी तक उनमें से किसी को अमल में नहीं लाया गया है।

पूर्वी लाइन पर चार सर्वेक्षण किये गये हैं जिनमें से एक की स्वीकृति दी गई है और दूसरे की शीघ्र ही मंजूरी दी जानी है। दो को मंजूरी देने में प्रगति हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में एक भी सर्वेक्षण ऐसा क्यों नहीं है जिसपर अमल किया गया हो ? मुझे खुशी है कि उत्तरी लाइन पर पोकरण-जैसलमेर लाइन को पूरा कर दिया गया है।

दक्षिणी लाइन पर तीन सर्वेक्षणों के प्रतिवेदन आए हैं। उनमें से किसी पर अमल नहीं किया गया है।

दक्षिण-पूर्वी, पश्चिमी लाइन पर पांच परियोजनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता हैं कि कटक पारादीप लाइन के निर्माण की, जिस पर 23 लाख रूपये खर्च होंगे, स्वीकृति दे दी गई है। उस पर कब अमल होगा इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इन त्रुटियों को दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इन सांकेतिक अनुदानों के लिये सभा की सहमति प्राप्त करने के हकदार हैं ?

एक सांकेतिक अनुदान 86 लाख रूपये का है जो फरक्का पर पुल बनाने के बारे में है। मैं मानता हूं कि इसका निर्माण करना जरूरी है परन्तु यह बात उन्हें सामान्य बजट के समय क्यों नहीं सूझी ? 2 मास बाद सामान्य बजट फिर पेश किया जाना है। इसे उसके साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। यह सर्वेक्षण भी पूरा नहीं होगा क्योंकि पुल के ऊपरी ढांचे पर होने वाले व्यय की व्यवस्था नहीं की गई है।

रेलवे मंत्रालय को इन स्थायी परियोजनाओं के लिये धन की स्वीकृति के लिये चोर दरवाजे का सहारा नहीं लेना चाहिये। मेरा रेलवे मंत्री से निवेदन है कि वे इस अनुपूरक बजट वापस को ले लें और अगले सामान्य बजट के पेश किये जाने तक प्रतीक्षा करें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर)। जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिये 55–60करोड़ रूपये की लागत से बेलाडीला से विशाखपत्तनम तक एक लाइन बिछाई गई है। इस लाइन पर न ही कोई गांव है और न ही कोई नगर है। केवल लौह अयस्क ढोने के अलावा इस लाइन पर कोई यात्री या माल यातायात भी नहीं है। जब हमारे देश में इस्पात कारखाने या ध्वन भट्टियां चालू हो जायेंगी और हमें लौह अयस्क का निर्यात नहीं करना पड़ेगा तब यह लाइन बिलकुल बेकार हो जायेगी। मैं नहीं जानता सरकार ने इस लाइन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया है।

अब सरकार का प्रस्ताव इस लाइन का विद्युतीकरण करने का है। इस पर 25 करोड़ रूपये खर्च होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि बेलाडीला से कोवुर और भद्राचलम तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाये। यह लाइन दण्डकारण्य वन के बीच से हो कर गुजरेगी। इससे रेलवे को माल तथा यात्री यातायात मिलने के अलावा आदिम जातीय लोगों को काफी मदद मिलेगी जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इसलिये विद्युतीकरण पर 25 करोड़ रुपये खर्च करने की बजाय इस लाइन को बिछाना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। कोठागुडम कोयला खानों से बहुत कोयला निकलता है और उसे अन्य क्षेत्रों को ले जाना होता है। राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई लाइन बनाने से उसे आसानी से अन्य क्षेत्रों को ले जाया जा सकता है। यदि यह लाइन नहीं बिछाई जायेगी तो आंध्र प्रदेश के लोगों में असंतोष फैलेगा।

पूर्व रेलवे के बंडल-कथुआ सैक्शन पर भारी यातायात है। सरकार ने अब तक इस सैक्शन के विद्युतीकरण के बारे में नहीं सोचा है। यदि इस काम में देरी होने की संभावना है तो रेलवे मंत्री को इस लाइन पर एक डीजल गाड़ी चालू करने के बारे में विचार करना चाहिये था।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण कराया है। मैं अनुरोध करूंगा कि वह कन्याकुमारी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये कार्यवाही करें इस कार्य में पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। इस बारे में सर्वेक्षण तो पहले ही किया जा चुका है। वह इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करायें क्योंकि रेलवे लाइन न होने से भारी संख्या में वहां जाने वाले तीर्थ–यात्रियों तथा पर्यटकों को बड़ी परेशानी हो रही है। मंत्री महोदय इस समस्या पर विचार करें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि गत हड़ताल के बाद से रेलवे कर्मचारियों में वह मैत्री की भावना नहीं रही है जिसके परिणामस्वरूप रेलों के यातायात में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। इस का कारण यह है कि गत हड़ताल के दौरान सरकार की कार्यवाही के कारण 10,000 से अधिक लोगों की नौकरी

समाप्त हो गई तथा अनेक रेलवे कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया । इससे रेलवे कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है और इसी कारण परस्पर सहयोग की कमी है । मेरा सुझाव है कि मंत्री इस संदर्भ में सामान्य वातावरण उत्पन्न करें ताकि रेलवे कर्मचारियों अधिक उत्साह और कुशलता से कार्य करें ।

मंत्री महोदय ने आग बुझाने वाले कर्मचारियों के विवाद को बड़ी कुशलता से शान्त किया था । यद्यपि मंत्री महोदय ने एक संसद सदस्य को लिखा है कि रेलवे कर्मचारियों के प्रति कोई शोषण की भावना नहीं रखी जायेगी परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि सियालदह सेक्शन के लगभग 450 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाल दिया गया है । इसके अतिरिक्त निलम्बित करने, चार्ज-शीट लगाने तथा नौकरी से अलग करने के भी अनेक मामले हुए हैं । इसके परिणाम स्वरूप मंत्री महोदय के अपने ही क्षेत्र के इन लोगों में कुछ कटु भावनायें उत्पन्न हो गई हैं । मंत्री महोदय को वहां सामान्य स्थिति स्थापित करनी चाहिए ।

ग्रान्ड ट्रंक एक्स्प्रेस की भोजन-कार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को गरम वर्दी नहीं दी गई है । उनको बड़ी सर्दी में अपना कार्य करने में बड़ी कठिनाई होती है । इन गरीब बैरों के बारे में भी मंत्री महोदय विचार करें । मैं जानता हूँ कि वह रेलवे कर्मचारियों के प्रति बड़े कृपालु हैं परन्तु कागजात उन तक नहीं पहुँच पाते रेलवे आयोग में ही एक स्तर तक पहुंचकर रुक जाते हैं ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जैसा कि वायदा किया गया था, बम्बई और कोचीन के मध्य प्रति दिन एक गाड़ी चलनी चाहिये । दक्षिण भारतीयों को इसकी शीघ्र आवश्यकता है । दूसरे हमारी इच्छा थी कि वैस्ट कोस्ट एक्स्प्रेस तिरूप्पुर रूके परन्तु रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह मांग स्वीकार करने से ऐसी ही और अनेक मांग की जायेंगी । मंत्री महोदय कृपया इस बारे में कोई प्रबन्ध करें ।

✓ **Shri Prem Chand Verma** (Hamirpur) : This House never objects on the demands of grants if the money is spent for a right and good cause. It is therefore essential to ensure that the money should be spent in a proper manner since this money comes out of the pockets of uor poor countrymen. And also that this money should be utilised for providing facilities to the poor railway travellers.

Secondly, there will not be any need to ask for supplementary grants if adequate steps are taken to protect the railway property from theft etc. Besides this all sorts of wastage should be checked and stopped. The hon. Minister should pay adequate attention towards this.

My next point is that my State, Himachal Pradesh, is now spread over a big area but there exists only a 150 mile long railway and that too a metre gauge railway line. The speed of railways is also very slow there. You have to spend a very little amount to construct a 10 mile long railway line from Nangal to Una and this can be very easily done if you are able to check the loss of railway property elsewhere.

Railway line between Pathankot and Jogindernagar is said to be running in a loss and therefore, you propose to close it down. But may I say that until you provide a broad-gauge line here and arrangement for transportation of big machines and equipment

for the wood, oil, paper and cement industry there, no industries can be set up and you cannot remove the poverty there ?

Himachal pradesh is the most backward area today and if we want to make it a prosperous and happy state, the supplementary demands should be rightly used and a broadgauge railway line between Nangal and Una should be constructed.

श्री चं० चु० देसाई (साबर कंठा) : जहां मैं रेल मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उसने सौराष्ट्र में यातायात सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराने की परियोजनायें हाथ में ली हैं, वहां मुझे आश्चर्य है कि मोडास, कापडवंज तथा टिटोई को जोड़ने वाली परियोजना को शामिल नहीं किया गया है यद्यपि इस बारे में हमने मंत्रालय से इस बारे में काफी लिखा-पढ़ी तथा अनुरोध किया था । हमने इस बारे में आंकड़े भी दिये थे कि वर्तमान रेलवे लाइन की अपेक्षा इस लाइन पर बहुत अधिक यातायात उपलब्ध होगा । अत: मैं मन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह मोडासा को कापडवंज अथवा टिटोई से जोड़ने का प्रबन्ध अवश्य करें ।

अनुपूरक मांगों में तारापुकर-भावनगर परियोजना का कहीं उल्लेख नहीं है जबकि इस बारे में सर्वेक्षण भी हो चुका है और इस पर कार्य भी आरम्भ होने वाला है । इस लाइन का निर्माण वर्ष 1947 से विचाराधीन है । मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ? इस लाइन का महत्व इसलिये भी अधिक है कि यह खम्बात आदि के तेल क्षेत्रों से गुजरती है । अतः इस लाइन का निर्माण होने से काफी सामान ढोया जा सकेगा तथा तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर इस क्षेत्र का मार्ग खुल जायेगा ।

मन्त्री महोदय द्वारा प्रदर्शित अवलम्बनीयता की भावना तथा अनुपूरक मांगों में ही नई परियोजनाओं को शामिल करने के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ ।

तालचेर-धर्मनगर लाइन का सर्वे वर्ष 1946 में हुआ था और यह लाइन रांची, रूरकेला, जमशेदपुर तथा तालचेर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरती है । हमें उद्योगों को जोड़ने वाली लाइनों की अधिक आवश्यकता है । मैं जानना चाहूँगा कि इस लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं मन्त्री महोदय के इस प्रयत्न की सराहना करती हूं कि उन्होंने प्रारम्भिक इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण कराया है, परन्तु मुझे खेद है कि सात वर्ष पूर्व कोंकण को दिये गये वचनानुसार वह परियोजना शामिल नहीं की गई । यद्यपि इस परियोजना के लिये मन्त्री महोदय स्वयं वहां गये थे परन्तु फिर भी अभी तक उस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया । गोआ आज राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार गोआ के लिये बहुत कुछ कर रही है परन्तु दूसरी ओर यह भी खेद है कि गोआ के 22 लाख निवासियों के लिये न तो वर्ष भर प्रयोग किया जा सकने वाला कोई पत्तन है और न ही कोई रेलवे लाइन ही है । हालांकि इस सन्दर्भ में सब से पहले ही आश्वासन दिया गया था । अतः मन्त्री महोदय वहां एक सर्वेक्षण दल भेजें क्योंकि वहां हम दो-तीन वर्षों में एक एल्यूमूनियम कारखाना स्थापित करने की आशा रखते हैं ।

इस्पात मन्त्रालय ने मुझे एक नोट में बताया है कि सारी परियोजना बिल्कुल तैयार है परन्तु बिना रेलवे लाइन के वे यह संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते। अतः यदि गोआ में कोई आर्थिक प्रगति करनी है तो उच्च स्तर पर यथेष्ट समन्वय होना चाहिए। हम अपने लोगों को इस बात का उत्तर देने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि वचन देकर भी सरकार यह कार्य क्यों नहीं कर रही।

यह सुझाव दिया गया है कि वह पहाड़ी क्षेत्र है तथा वहां रेलवे लाइन बिछाने पर बड़ी लागत आयेगी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रति व्यक्ति क्या खर्च आयेगा। क्या यह जानने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि गोआ के 22 लाख लोगों पर प्रति व्यक्ति क्या खर्च होगा। क्या उन्हें परिवहन का कोई अन्य साधन उपलब्ध है ? क्या मन्त्री महोदय कम से कम यह आश्वासन देंगे कि वह वहां एक अध्ययन दल भेजेंगे ?

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : रेलवे विभाग में कुप्रबन्ध के कारण यह विभाग विभिन्न कारणों को लेकर प्रायः ही अनुपूरक मांगें पेश करता रहता है। और इसी कारण यह विभाग यात्रियों और अपने कर्मचारियों पर बोझ डालता है। इस वर्ष से अकारण रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने पर जुर्माने की राशि 50 रुपये से बढ़ा कर 250 रुपये कर दी गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि जंजीर खींचने की घटनायें घटी हैं अथवा बढ़ी है। वास्तव में इस कानून के बाद यह संख्या बढ़ी है। परन्तु रेलवे विभाग अपनी अव्यवस्था के वशीभूत हो नये नये कानून बनाये जा रहा है। अभी हाल ही में रेलवे में सुप्रबन्ध की बात लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया है। जिसका मूल अर्थ तो कर्मचारियों को दण्ड देना है। भारत पूर्व रेलवे देश का सबसे घना क्षेत्र होते हुए भी बड़ा अकुशल है। उसके मार्गों पर यात्री पायदानों अथवा डिब्बों व इन्जनों की छतों पर यात्रा करते हैं जिससे बहुत सी दुर्घटनायें भी होती हैं। रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री प्रायः इस मार्ग पर यात्रा करते है और वह इस स्थिति से अवगत है। परन्तु क्या रेल विभाग इन लोगों के जीवन की चिन्ता करता है ? कुछ नहीं। इस मार्ग पर चलने वाली अनेक गाड़ियों में केवल 4–4 डिब्बे हैं। गाड़ियों की संख्या भी बेहद अपर्याप्त है। भीड़ कभी भी कम नहीं होती। रोज यही होता है।

इसी कुप्रबन्ध के कारण रेलवे विभाग की आय घट रही है। इसी कुप्रबन्ध के कारण अत्यन्त गरीब लोगों को भी अपने परिवार आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु अन्य परिवहन साधनों पर कई गुना अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। इसीलिये अनेक लोग बिना टिकट भी यात्रा करते हैं। परन्तु रेलवे विभाग इस पर कोई विचार नहीं करता। इस विभाग ने सुविधा कोई दी नहीं और भाड़े में वृद्धि करता रहा है। पूर्व रेलवे के सियालदह खण्ड में डिब्बों के अन्दर बिजली, पंखा आदि कुछ भी नहीं है। वहां बैठने तक को स्थान नहीं है।

कुछ निहित स्वार्थों के कारण हसनाबाद से बारासात लाइन के पूर्व स्वीकृत मार्ग को बदल दिया गया है। जिससे कि रेलवे विभाग को आर्थिक हानि होगी। मेरा सुझाव है कि इस मार्ग पर स्टेशन इस प्रकार स्थापित किये जाये कि आस–पास के गांव तथा पक्की सड़क उनके निकट पड़ें।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भारतीय रेलवे को अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, यह सब संकट रेलवे के विकास में एक ही तरफ ध्यान देने से उत्पन्न हुआ है। उद्योग रेलवे पर आधारित है, अतएव इस विचार से प्रेरणा पाकर रेलवे ने कई योजनाएं बड़े पैमाने में हाथ में ली। रेलवे का आधुनिकीकरण और विकास करते समय वे इसके आर्थिक पहलू की ओर ध्यान देना भूल गए। इस प्रकार रेलवे की माल ढोने और यात्री ले जाने की क्षमता तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद औद्योगिक उन्नति से आगे बढ़ गई, परिणामस्वरूप रेलवे में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। आज रेलवे में यह वित्तीय संकट सबसे अधिक अनुभव किया जा रहा है, यह पाया गया है कि रेलवे की कार्य प्रणाली में कुछ ऐसे दोष हैं जिनको दूर करना आवश्यक है, मैं मन्त्री महोदय को इनको दूर करने के लिए कुछ सुझाव दूंगा। पहला, इसकी कार्य प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाये जिससे कि मौजूदा व्यक्तियों और उपकरणों का अच्छा उपयोग किया जा सके। दूसरा, जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता तब तक नई लाइनें बिछाना तथा अन्य कार्य हाथ में न लिये जायें, तीसरा, ईंधन का इस प्रकार से उपयोग किया जाये कि इसमें लागत कम आये, चौथा, बिना टिकट यात्रा करने वालों को निरुत्साहित किया जाये।

रेलवे सुरक्षा दल और सतर्कता संगठन को भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। रेलवे सामान और उपकरणों की चोरी और उठाईगिरी रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि खोये तथा नुकसान हुए माल की क्षतिपूर्ति बहुत देनी पड़ती है। अगर इसको रोका नहीं गया तो रेलवे को बहुत नुकसान होगा। 'राजधानी एक्सप्रेस' जैसी नई रेलगाड़ियां नहीं चलायी जानी चाहिए अपितु जनता रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए क्योंकि इसी से सरकार को काफी आय प्राप्त होती है।

बंदेल–कटवा लाइन एक महत्वपूर्ण लाइन है और इसको हाथ में लिया जाना चाहिए।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : मैं सर्वप्रथम त्रिवेन्द्रम–अन्तरीपतिरुनेलवेली लाईन का प्रश्न उठाना चाहूंगा। केरल और तामिलनाड के लोग इसके लिए बहुत समय से मांग करते रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षण किया गया और मन्त्री महोदय ने मुझे यह लिखा है कि इस लाइन का बिछाना अलाभप्रद रहेगा। मैं यह कहूँगा कि यह गलत मूल्यांकन है। कन्याकुमारी एक तीर्थ स्थान है और साथ ही पर्यटक केन्द्र भी है यहां जाने के लिए लोगों को तिरुनेवेली अथवा त्रिवेन्द्रम जाकर फिर बस पकड़नी होती है। यह पवित्र स्थल है और तीन समुद्रों का संगम होता है, अतएव यह आवश्यक है कि शेष भारत के साथ इसे रेल द्वारा जोड़ा जाये।

रेलवे मन्त्रालय ने एक और तर्क दिया है कि टूटीकोरिन पत्तन के विकास के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा, परन्तु यह एक भ्रामक तर्क है, त्रिवेन्द्रम जिले के विजीजैम में एक बन्दरगाह बन रहा है, जब यह दोनों बन्दरगाह बन कर तैयार हो जायेंगे, तो इनके बीच रेल सम्पर्क न होने का प्रश्न आयेगा। मैं गत वर्ष कांडला गया था तो वहां के लोगों ने पत्तन के साथ बड़ी लाइन द्वारा रेल का सम्बन्ध न होने की शिकायत की थी, अतएव मैं कहूंगा कि इस लाइन पर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाये।

मैं एर्णाकुलम–त्रिवेन्द्रम लाइन के सम्बन्ध में भी कहना चाहूँगा। विशेषकर एर्णाकुलम से क्विलोन को छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यह क्षेत्र निर्यात की जाने वाली कई वस्तुएं पैदा करता है, और यह वस्तुएं कोचीन बन्दरगाह में निर्यात के लिए लाई जाती है। इसी तरह भारत के अन्य भागों में भेजी जाने वाले रबड़ का उत्पादन भी यहां होता है, यहां छोटी लाइन का निर्माण करना एक गलत कार्य था। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य हाथ में शीघ्र लिया जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं रेलवे में आधान (Contain erisation) की सेवा आरम्भ करने के लिए बधाई देता हूं। सम्भवतः जापान को छोड़ कर एशिया में हमारे देश में यह सेवा आरम्भ की गई है। मैं यह सिफारिश करूंगा कि पश्चिम रेलवे में तेज चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए और अधिक डीजल–इन्जन प्रयोग किये जाने चाहियें क्योंकि गुजरात में डीजल तेल बहुत मिलता है।

मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि पश्चिम रेलवे में सबसे छोटी (narrow) रेलवे लाइनों को छोटी लाइन अथवा बड़ी लाइन में बदला जाये, और जब इन छोटी लाइनों पर चलने वाले इन्जन न काम कर सकें तो डीजल से चलने वाले छोटे इन्जन चलाये जायें जैसा कि बड़ौदा राज्य रेलवे ने किया था।

बिना टिकट यात्रा करने वालों से भी रेलवे को काफी हानि उठानी पड़ती है, रेलवे ने इसकी रोकथाम के लिए ऐसी सेवाएं, जो स्वैच्छिक रूप से दी जाती है, लेनी आरम्भ कर दी हैं। यह एक अच्छा कदम है। हमें कलकत्ता, मद्रास और अन्य दूर–दूर स्थानों के लिए तेज चलने वाली रेलगाड़ियां अधिकाधिक चलाई जानी चाहियें, यह खुशी की बात है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच राजधानी एक्सप्रैस चलाई जा रही है।

रेलवे ने डीलक्स रेलगाड़ियां चलानी आरम्भ की हैं जिनके तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे है। मैं रेलवे को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि वे तृतीय श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, तृतीय श्रेणी के यात्रियों को यह शिकायत है कि टिकट खरीदने पर भी बैठने को जगह नहीं मिलती, मैंने कई वर्ष पूर्व यह सवाल इस सभा में भी उठाया था कि सिनेमा का टिकट खरीदने पर वहां बैठने को जगह मिल जाती है परन्तु रेल का टिकट खरीदने पर बैठने को जगह नहीं मिलती और यात्रियों को छत पर बैठना पड़ता है।

मांग नम्बर 14 के बारे में मैं यह सुझाव दूंगा कि दिल्ली और कलकत्ता के मध्य बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाई जायें। मांग नम्बर 15 के बारे में मैं यह कहूंगा कि रेलवे में और अधिक मितव्ययिता की जाये क्योंकि यह आय कमाने वाला मंत्रालय है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I oppose the supplementary demands because the Government have not undertaken many other important works.

According to the rules of Railway travel on footboard is punishable, But passengers travel on footboard in Bombay city. It is a long-standing demand to increase the number of suburban trains and also there is a demand to extend the lines of Western and Central Railways, But judging from the pace of work of Railway Ministry it seems that nothing will be done in the coming years.

The former Railway Minister Shri S. K. Patil always talked about Underground Railway in Bombay. Shri Patil gave all such assurances just to get votes but nothing has been done in this direction. I want to say that work on construction of the Underground Railway should be undertaken without further delay. Facilities should be made available to the railway passengers, I have all along been stressing that 100 more trains can be provided if the A. C. C. First class, Second class and particulary the 900 saloons run for the Railway Minister, Members and Officials of the Railway board are abolished.

The security of the country is very much linked with the Railways. I want to say that there is a demand for Broad gauge Railway line in kutch so that there may be no difficulty for our forces to much to the area in case of aggression.

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे अनुदानों का समर्थन करते हुए एक-दो बातें रेलवे मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं ।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे चलाने के बारे में आश्वासन दिया गया था परन्तु इसके बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया । मेरी प्रार्थना है कि इस पर भी विचार किया जाये। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगी कि बांदेल कटवा लाइन पर बहुत भीड़-भाड़ रहती है और काफी समय से वहां विद्युतीकरण का आश्वासन दिया गया था परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया । कम से कम इस लाइन को दोहरी कर दिया जाये ताकि वहां यात्रा करने वाली जनता को कुछ राहत मिल सके । तीसरा, मैं देवग्राम स्टेशन में उपरिगामी पुल के बारे में कहना चाहती हूं । इसका आश्वासन कई वर्ष पूर्व दिया गया था और यह मामला सलाहकार समिति के सामने भी आया था । मुझे आशा है कि अब इस पर ध्यान दिया जायेगा । ये छोटी छोटी बातें हैं और इसमें अधिक खर्चा भी नहीं आयेगा ।

दार्जिलिंग में भूस्खलन आदि से रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ा, अतएव वहां यह आशंका फैली हुई है कि शायद रेलों का चलना बंद हो जायेगा । मुझे आशा है कि ऐसा नहीं किया जायेगा । क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचेगी । जलपाईगुड़ी में रेलवे ने पूरी तरह काम करना शुरू नहीं किया है । अभी वहां पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे आशा है कि पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई जायेगी और चाय के उद्योग को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : It is a common thing that the Government do not pay attention to any suggestions that are given

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर छः मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Six minutes past Fourteen of the Clock.

{ श्रीवासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair* }

छात्रों में असंतोष के बारे में चर्चा
DISCUSSION REGARDING STUDENT UNREST

सभापति महोदय : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की घटनाओं के संदर्भ में नियम 193 के अन्तर्गत छात्रों में असंतोष के बारे में चर्चा की जायगी। इसके लिए दो घंटे नियत किए गये हैं, श्री रा० की० अमीन इस चर्चा को आरम्भ करें।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : देश के विभिन्न भागों से छात्रों द्वारा हिंसा करने के मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों से भी छात्रों द्वारा उपकुलपति के घेराव, बसों को जलाना, ईंट पत्थर फेंकने आदि के समाचार मिल रहे हैं। यह घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में भी हो रही है। अतएव प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और हमारे छात्रों में ऐसा कौन सा दोष है ?

आखिर इस अशान्ति के पीछे मूल कारण क्या है और जब हमें इस कारण का सही सही पता लग जाये, तो फिर उसका निराकरण करना उतना कठिन व असम्भव नहीं रहेगा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे और संभवत वह सभी परिस्थितियों के विश्लेषण का संकेत करता है। यद्यपि शिक्षा मंत्री इस कदम का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने मामले की जांच करने के लिए विजिटर द्वारा समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है, तथापि उनकी इस सम्बन्ध में जो ढुल मुल नीति रही है उसकी सराहना नहीं की जा सकती। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में दूसरी बात यह है कि राजनीतिज्ञों पर विभिन्न आरोप लगाये गये हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों पर आरोप लगाया गया है कि वे इस विश्वविद्यालय के काम में हस्तक्षेप करते हैं, एक ओर तो हम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात करते हैं और दूसरी ओर हम उसके कार्यों में पीछे से दखल देते हैं, अर्थात् उसकी स्वायत्तता का आदर नहीं करते। हमारे दिमाग में स्वायत्तता की जो कल्पना अथवा धारणा है वह भी कुछ गलत है। स्वायत्तता अध्यापकों की स्वायत्तता होनी चाहिए और न कि राजनीतिज्ञों की जो चोर दरवाजे से घुसते हैं। हम देखते हैं कि कई मामलों में हारे हुए राजनीतिज्ञों को विश्वविद्यालय का उप कुलपति नियुक्त किया जाता है जो देश के राजनैतिक जीवन में खुले आम भाग लेते हैं, शिक्षा मंत्री, श्री त्रिगुण सेन ने कहा है कि वह जांच समिति नियुक्ति करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन वह ऐसा करके अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं।

उन्हें सामाजिक परिवर्तन तथा समाज की भलाई के लिये जो भी आवश्यक हो, करना चाहिए। उन्हें वह हर कदम उठाना चाहिए जिससे स्वायत्तता का उसके असली माने में सम्मान हो, उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को चुनौती देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अनुशासन बनाये रखें और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर वे अध्यापक बनने के योग्य नहीं हैं। जहां तक राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है, इस विश्वविद्यालय में आये दिन गड़बड़ी के कारण स्वायत्तता की गलत भावना तथा स्वायत्तता के प्रति प्रदर्शित आदर का गलत ढंग रहा है।

विद्यार्थी बहुत संवेदनशील मस्तिष्क के होते हैं। उन पर हमारे बर्ताव तथा गतिविधियों का तीव्र प्रभाव पड़ता है और वे उसका बढ़ा चढ़ाकर अनुकरण करते हैं जब वे देखते हैं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद का चारों ओर बोलबाला है, सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं और सरकार उनके प्रति कैसा रुख अपनाती है, और लोक-सभा में जो कुछ होता है तथा हमारा जैसा बर्ताव रहता है, उसकी उन पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है और उनके मस्तिष्क पर बुरी धारणा अंकित होती है, यही कारण है कि वे आज हमारे बुरे कामों की तीव्रता से नकल कर रहे हैं। हमने इस जिम्मेदारी को ग्रहण करना चाहिए और हमारे निदान में उसके नुसखे का भी संकेत होना जरूरी है।

छात्रों में अनुशासनहीनता के दो और कारण हैं। एक कारण तो स्वतः अध्यापक ही हैं। बहुत से अध्यापक ऐसे हैं, जो अध्यापक बनने के काबिल ही नहीं हैं। मेरा निजी अनुभव यह है कि यदि किसी अध्यापक में वास्तव में अध्यापक के गुण हों, और वह छात्रों को सुशिक्षा देता है और ज्ञान का प्रसार करता है, तो आवारा प्रकृति का छात्र तक उसकी कदर करता है और उसके सामने ऐसा कोई काम नहीं करता जो बुरा हो। विशेषकर रिहायसी विश्वविद्यालय में तो केवल अध्यापक ही अनुशासन रख सकता है। लेकिन होता यह है कि अध्यापकों में भाई भतीजावाद तथा क्षेत्रीय भावनाओं के शिकार रहते है जिससे वे अनुशासन नहीं बनाये रख सकते। उदाहरणार्थ, बनारस विश्वविद्यालय में किसी विशेष क्षेत्र के अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं और भाई-भतीजेवाद का बोल-बाला रहता है जिसका छात्रों के मस्तिष्क पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अध्यापन व्यवसाय में हमने अच्छे तथा योग्य अध्यापकों को आकर्षित करने की दिशा में कुछ नहीं किया है। यह आवश्यक है कि देश में उपलब्ध योग्य व्यक्तियों की एक निश्चित प्रतिशतता अध्यापन कार्य में लगी होनी चाहिए और इस कार्य के लिये सरकार को समुचित पग उठाने चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में इस बहुत बड़ी कमी को दूर किया जा सके।

दूसरा कारण शिक्षा का ढ़ांचा है। बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो वास्तव में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के योग्य होते हैं। लेकिन सरकार ने उनके लिये किसी विकल्प की व्यवस्था नहीं की है, जो एस० एल० सी० पास करने के बाद कालेजों में प्रवेश करना चाहते हैं किन्तु उसके योग्य नहीं होते क्योंकि वे और कहीं जा नहीं सकते। देश में पोलीटेक्निक किस्म की शिक्षा व्यवस्था नहीं है जहां वे जा सकें और शिक्षा के साथ-साथ अर्जन भी कर सकें जैसा कि इंगलैंड तथा अमरीका में होता है। देश में प्रातः तथा सायं कक्षाओं की व्यवस्था तथा पत्राचार पाठ्यक्रम भी नहीं है जहां शिक्षा तथा अर्जन दोनों साथ-साथ चल सके और विश्वविद्यालय

में केवल वे ही छात्र जायें जो वहां प्रवेश पाने के योग्य हों। जब तक शिक्षा के ढांचे में सुधार न किया जाये, अध्यापक अपने व्यवसाय के योग्य न हो और उसमें उस व्यवसाय के लिये अपेक्षित गुण न हो और स्वतः हम अपने को न सुधारें, स्थिति में सुधार होना संभव नहीं हो सकता। हो सकता है छात्रों में मूलतः कोई दोष न हो, लेकिन इन बातों के कारण समाज की नजरों में वे गलत दिखाई देते हैं।

जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की समस्या का सम्बन्ध है, इसका एक मात्र हल यही है कि वहां दाखिले बन्द कर दिये जाये और आगे कोई दाखिला न दिया जाये। अध्यापकों से खुद हल ढूंढ़ने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये कहा जाये और उनसे कहा जाय कि यह तुम्हारे लिये एक चुनौती है और यदि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते, तो आपको पब्लिक खर्च पर अध्यापक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही दृष्टिकोण अपनाया जाये, तो संभव है की बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उपद्रवों की समस्या हल हो जाये।

न्यायिक जांच केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये ही नहीं होनी चाहिए। इसमें समूची शिक्षा पद्धति की शिक्षा मंत्री से लेकर जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी शामिल हो, विश्वविद्यालयों के आदर्श अधिनियमों तक की जांच की जानी चाहिए। जब तक व्यापक रूप से जांच नहीं की जाती, शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं हो सकता, और जब तक उसमें सुधार नहीं होता, संभवतः अनुशासनहीनता समाप्त नहीं होगी और एक छोटा कारण भी छात्रों को उत्तेजित करता रहेगा।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : जहां तक छात्रों में अशान्ति का सम्बन्ध है, वह सामाजिक व्यवस्था के आडम्बर, तथा आज के समाज में असमानता, भ्रष्टाचार तथा ऐसी ही अन्य बुराइयों के विरुद्ध एक क्रान्ति है। फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी ऐसा हुआ है, जब तक हम अपने समाज को न सुधारें, छात्रों में क्रांन्ति की यह प्रवृति बनी रहेगी।

महत्वपूर्ण तथा सम्बद्ध प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों के वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत इन सभी उपद्रवों का हल कैसे ढूंढा जाये। हमारे इस ढांचे में कई ऐसे कानून हैं जिनसे विश्व-विद्यालय में अध्यापक तथा अन्य कार्यकर्ता अनुचित लाभ उठाते हैं और इन पर हमें बड़ी सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में पदों के विभाजन तथा इन पदों के लिये उपकुलपति पर डाले जा सकने वाले दबाव के प्रश्न पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ इस प्रश्न पर भी विचार करने की जरूरत है कि बहुत से मामलों में पदों के लिये निर्वाचन करना अत्यावश्यक है। एक शिक्षा संस्था में जहां पाठ्यक्रम तथा अन्य मामलों के बारे में शिक्षा सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय लेना होता है, जैसा एक व्यक्ति काम कर सकता है वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। इसलिये इन पदों के लिये पर्चियां डालकर लोगों का चयन क्यों न किया जाये। विश्वविद्यालयों में जो कुछ होता है वह केवल छात्रों के कारण ही नहीं होता, बल्कि उन्हें राजनीतिज्ञों अथवा अध्यापकों या अन्य लोगों द्वारा किसी प्रयोजन से घसीटा भी जाता है। हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे हों, जो अशान्ति पैदा करना चाहते हैं किन्तु वे थोड़ी संख्या में होते हैं और जिन्हें केवल छात्रों की

बहुसंख्या में अनुपात की भावना से ही नियंत्रित किया जा सकता है। यह जांच कराने अथवा यह मालूम करने का प्रश्न नहीं है कि उपद्रव किसने किसने शुरु किया। प्रश्न यह है कि अध्यापक स्वतः स्थिति पर काबू कैसे पा सकेंगे। अध्यापक स्थिति पर काबू पा सकते हैं बशर्ते वे पहल लें, वे पहल भी ले सकते हैं किन्तु वहां शिक्षा सम्बन्धी ऐसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे कि वे ठीक समय पर पहल ले सकें। इसलिये इस दिशा में अपेक्षित प्रयास करना आवश्यक है।

जब छात्रों के एक दल ने कुछ किया, तो कोई कार्यवाही नहीं की गई और जब छात्रों के दूसरे दल ने वही काम किया तो कुछ कार्यवाही की गई। मैं नहीं समझ पाता कि इसका स्पष्टीकरण वह किस प्रकार देते हैं। मैं इस मामले में राजनैतिक दलों को बीच में नहीं लाना चाहता, किन्तु जब तक उपकुलपति अथवा शिक्षा संस्थाओं के प्रधान इन मामलों में तटस्थ नहीं रहते, सरकार को उनके साथ कड़ाई से व्यवहार करना चाहिए और आवश्यकता हो, तो उन्हें अनुशासनबद्ध भी करना चाहिए।

उदाहरणार्थ, शिक्षा मंत्री को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति से जांच आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में उसके सदस्यों के बारे में आग्रह करना पड़ा है। जब शिक्षा मंत्री जांच कराना चाहें, तो उन्हें खुद अपने निर्देश देकर जांच करानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि अधिनियम में क्या रुकावटें हैं, लेकिन जब संसद किसी केन्द्रीय विद्यालय के कार्यों के बारे में जांच कराना चाहती है, तो ऐसे आंयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : छात्रों में अशान्ति की समस्या कोई नई बात नहीं है। यह समस्या लगभग सभी देशों में मौजूद है और कुछ हद तक वह स्वाभाविक है। नवयुवक अपनी शक्ति के प्रयोग के लिये कुछ क्षेत्र चाहता है और जब वह क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता, जब उसका आदर्श सुव्यवस्थित मार्ग नहीं मिलता और जब वह निराश हो जाता हैं तो वह फिर कुछ तरीकों का आश्रय लेने की सोचता है हो सकता है, जो यथापूर्व स्थिति के समर्थकों को पसन्द न हों।

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आम तौर पर हमारे विद्यार्थी अच्छे हैं, वे समझदार हैं तथा अनुशासन का पालन करने वाले हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि उनकी योग्यताओं को और उनकी शक्तियों को रचनात्मक कार्य में लगाने के लिये हमने क्या किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले छात्र स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेते थे और इस प्रकार उनकी शक्तियों का सदुपयोग हो जाता था। उस समय उनकी संख्या भी कम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा प्रणाली को नई दशा देने अथवा छात्रों को फालतू समय का इस्तेमाल करने के लिए अवसर देने के बारे में बहुत मामूली काम किया गया है। हर व्यक्ति जानता है कि छात्रों के पास फालतू समय बहुत होता है। उनमें शक्ति है। उनकी शक्ति का रचनात्मक कार्यों के लिये सदुपयोग किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वे अपनी शक्ति का उपयोग किसी और काम में करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वे स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेते थे,

और इस प्रकार उनकी शक्ति का सदुपयोग हो जाता था। परन्तु अब वह स्थिति नहीं है। अब उनकी शक्ति का इस्तेमाल करने के अवसर बहुत सीमित हो गये हैं। छात्र जानते हैं कि स्कूलों से निकलने के बाद उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। उनके सामने अन्धकार ही अन्धकार है। ये कुछ ऐसी परस्थितियां हैं, जिनमें वह युवक भी जो एक अच्छा युवक है, तथा जो अनुशासनहीनता को पसन्द नहीं करता, और जो अपनी शक्ति का उचित इस्तेमाल करना चाहता है, कभी-कभी निराशा का शिकार हो जाता है और ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने लग जाता है। अतः छात्रों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा।

छात्रों में अनुशासनहीनता और असंतोष का कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। गत बीस वर्षों में शिक्षा पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन करने के लिये क्या किया गया है? ब्रिटिश राज में सब राजनैतिक नेता शिक्षा पद्धति की आलोचना किया करते थे और कहा करते थे कि यह शिक्षा पद्धति ब्रिटेन की देन है और उन्होंने कलर्क पैदा करने के उद्देश्य से इसे बनाया है। परन्तु उसमें सुधार करने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। शिक्षा पद्धति और भी खराब हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यद्यपि शिक्षा में कोई राष्ट्रीय तत्व मौजूद न था, तथापि बाहर राष्ट्रीयता थी परन्तु अब न तो शिक्षा में ही कोई राष्ट्रीय तत्व है और न ही बाहर कोई राष्ट्रीय भावना। इन सब वर्षों में हम केवल जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर जोर देते रहे हैं, परन्तु देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। हम जीवन स्तर की बातें करते हैं, परन्तु जीवन की मान्यताओं को भूल गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज के साधारण विद्यार्थी की त्रिशंकु वाली स्थिति है। अतः इस स्थिति के लिये हमारी शिक्षा पद्धति दोषी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी वर्तमान स्थिति के लिये दोषी है। शिक्षा मंत्रालय ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहा है, जो शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते थे और जिनकी दिलचस्पी केवल राजनीति में होती थी।

आम तौर पर कहा जाता है कि राजनीति हमारे छात्रों को खराब कर रही है। महोदय, शिक्षक राष्ट्र की राजनीति में भाग लेते हैं और इससे अनुशासन को कोई ठेस नहीं पहुँचती, अपितु इसके विपरीत यदि शिक्षक राजनीति में भाग लेते हैं तो वे सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं और उनका सम्मान बढ़ जाता है तथा इस प्रकार वे छात्रों में और अच्छी तरह से अनुशासन कायम कर सकते हैं। वास्तव में कालेजों और विश्वविद्यालयों की आन्तरिक राजनीति ही इस सारे उपद्रव के लिये उत्तरदायी है। शिक्षकों और उपकुलपतियों तथा अन्य अधिकारियों को योग्यता के आधार पर नहीं; बल्कि जाति, प्रभाव और दबाव के आधार पर चुना जाता है। ऐसे अध्यापकों, उपकुलपतियों तथा प्रधानाचार्यों का नैतिक प्रभाव क्या हो सकता है और इसी कारण अनुशासन समाप्त होता जा रहा है। भारत के युवक को आदर्शवाद की आवश्यकता है। वह समझदार है तथा उस पर प्रभाव डालने के लिये ऊंचे स्तर के शिक्षक तथा उपकुलपति चाहियें। अतः उनको वे उपकुलपति कैसे प्रभावित कर सकते हैं, जिनका चयन योग्यता के आधार पर नहीं अपितु अन्य बातों के आधार पर किया जाता है। आज हमारे स्कूलों तथा कालेजों में प्रधानाचार्य क्या कर रहे हैं? वे केवल सामन्तशाही का रवैया अपनाये हुए हैं। वास्तव में प्रधानाचार्य को अधिक अच्छा शिक्षक होना चाहिये, परन्तु

कुछ स्कूलों में प्रधानाचार्य शिक्षण कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं, वे केवल प्रशासक का ही काम करते हैं। अतः ऐसे प्रधानाचार्य किस प्रकार छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

हम लोकतन्त्र की बात करते हैं। हम सार्वजनिक साझेदारी की बात करते हैं। आप छात्रों को मताधिकार नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते कि वे राजनीति में भाग लें। तो अब वे क्या करें ? आप उनकी सुविधाओं के बारे में भी उनकी सलाह नहीं लेना चाहते। मैं मानता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी मामलों में छात्रों का दखल नहीं होना चाहिये। इन बातों के सम्बन्ध में उपकुलपति, सीनेट अथवा शिक्षा परिषद् को ही निर्णय करना चाहिये। परन्तु मैंने कई मामलों में देखा है कि प्रधानाचार्य अथवा अधिकारी छात्रों की छोटी-छोटी और उचित मांगों को भी ठुकरा देते हैं। वे इस तरह बर्ताव करते हैं, जैसे इन मांगों का कोई महत्व ही नहीं है। फलतः छात्र विवश होकर अपना असन्तोष प्रकट करते हैं और कभी-कभी वे विद्रोह भी कर देते हैं।

इसके साथ-साथ हमने यह भी देखना है कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने छात्रों को दे रहे हैं। छात्र भी समाज का ही अंग है और वे समाज के वातावरण से प्रभावित होंगे। आज जब कि समाज में हर जगह अनुशासनहीनता है, तो छात्रों में अनुशासनहीनता क्यों नहीं होगी। आज संसद में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, राजनीतिक नेताओं का व्यवहार कैसा है, वयस्क व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, इन सब का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। जब इन सब में अनुशासनहीनता है, तो उनमें क्यों नहीं होगी।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कुछ राजनीतिक दल अथवा राजनीतिज्ञ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि लोकतन्त्रात्मक तरीके से अथवा संवैधानिक तरीके से वे सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यह खतरनाक तरीका अपना लिया है। इस खतरनाक तरीके का छात्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज जैसे पुलिस वाले गोली चलाने और लाठी चलाने के शौकीन हो गये हैं, वैसे ही छात्र भी पत्थरबाजी के शौकीन हो गये हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। हम राजनीतिज्ञों की इस सम्बन्ध में विशेष जिम्मेदारी है। हमें छात्रों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना चाहिये। उन्हें राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। वे समाज का एक अंग हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक छात्र को मताधिकार दिया जाना चाहिये। 21 वर्ष के अशिक्षित व्यक्ति से 18 वर्ष के छात्र को मताधिकार देना कहीं अच्छा है। आप उन्हें राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। छात्रों को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिये। उन्हें राजनीति को समझना चाहिये। किन्तु यह उनके भी हित में है तथा देश के भी हित में है कि उन्हें विश्वविद्यालय से निकलने से पहले दलगत राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि उनका किसी दल के प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग न किया जाये।

अब मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय भारत की पथ प्रदर्शक संस्था है। यह विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीयता और देश भक्ति का द्योतक और जनक था। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध था। परन्तु आज वहां क्या हो रहा है ? कुछ राजनीतिक दल वहां कठिन समस्यायें पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस ढंग से सम्पत्ति जलाई जा रही है और तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जा रही है, उससे पता चलता है कि उन्हें विश्वविद्यालय में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें

छात्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है । वे विनाश करने पर तुले हुये हैं । बनारस विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्रों ने अनुशासन का पालन किया है और वे आन्दोलन से दूर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । विश्वविद्यालय के बहुत थोड़े छात्रों ने इन घटनाओं में भाग लिया है । उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि नरमी से व्यवहार किया गया तो अपराध और भी बढ़ जायेंगे ।

मैं अन्त में सुझाव देता हूँ कि छात्रों में अविश्वास के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए शिक्षा, राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन से भलीभांति परिचित व्यक्तियों की एक समिति बनाई जानी चाहिये । उस समिति को इस समूचे मामले पर भली भांति विचार करना चाहिये और सुझाव देने चाहिये, जिन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूँ कि मेरा सुझाव स्वीकार किया जायेगा ।

Shri A.S. Saigal (Bilaspur) : I have been a student of Banaras Hindu University. I have studied there in 7th, 8th and 9th class. My brother was a college student at that time and I used to live with him. As such I have a personal knowledge about that University. At that time there was a system, when we used to go to school at 10 or 10.30 A.M. we used to attend prayers. Those prayers had a moral effect on the students. But that system is no longer in force. In this connection I want to quote Shri P.V. Gajendragadkar, Vice Chancellor of Bombay University. He had called upon the University Community to create a sense of ethes, a sense of purpose, a sense of dedication, to the cause of service of the community.

It is a fact that there have been cases of violence in Banaras Hindu University. The agitation is still going on. But it will not be proper to take strong action against the students. The students are very sensive and it will be wrong to take strong action against them. In this connection the Council of Banaras Hindu University has recommended the constitution of a Committee to look into the matter. The Committee will recommend meaures to improve discipline among the students. We should agree to this proposal.

We should not accuse any particular political party for student unrese. The students when grown up and free to follow any political thought. But so far as they are in Universities, they must remain under discipline. If you want to give the right to vote to the students, I have no objection in giving to it. But discipline is very necessary and must be ensured at all cost.

A memorandum has recently been presented to the President Dr. Zakir Hussain, regarding the affairs of Banaras Hindu University. Certain charges have been levelled in that memorandum. One of the charges levelled in the Memorandum is that the University has become a Centre of the R.S.S. It has also been alleged in the memorandum that instead of curbing indiscipline, lawless elements are being encouraged. The memorandum further, says that the atmosphere is surcharged with unacademic and unlawful activities, unbecoming of a great institution. So in view of such serious charges it is necessary that an enquiry committee is appointed to go into the whole matter and early steps are taken to improve the situation. If steps are not taken well in time, the situation is likely to deteriorate. The Government should give serious thought to this ma ter.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The question of Banars Hindu University is a very important one, because Banaras Hindu University is the biggest residential University in the country. Nearly 4000 students are living in that University and 12000 students are on its roll. The question of Banaras Hindu University has a special significance, because it is a Central University on which an amount of Rs. 2500 per annum per student is incurred by the Central Government. It is a matter of great regret that when the students of Banaras Hindu University come to the Education Minister to present their grievances, he paid no need to them and dismissed their submission by saying that it is a matter of discipline and accepted the recommendation of the Vice Chancellor for appointment of an Executive Committee to look into these problems. By doing so the Education Minister has failed to discharge his responsibility.

You all know that a majority of the students of Banaras Hindu University is against the Vice-Chancellor. It has been alleged that he has misused his office and has acted in a partisan way. The whole trouble in the Banaras Hindu University started with the election of the Union, when the Vice Chancellor tried to have a person of his own liking elected as the President of the Union. The Vice Chancellor went to the extent that he put up such a candidate for the Presidentship of the Union, who was not even eligible for seeking the election according to the rules of the Union. The students did not like the candidate put up by the Vice-Chancellor. They rejected him and elected their own independent candidate as President of the Union. The Vice Chancellor could not tolerate it. Not it is learnt that the Vice-Chahcellor has expelled that student from the University. This is the height of nepotism. How could there be any discipline in view of such things. The atmosphere there in the University is awful and murders are being committed there.

That is not all. There have been very serious incidents in the University Campus. At the time of the convocation three boy students misbehaved with two girl students, Their case was referred to the Court of Honour of the University. The Court of Honour of the University found them guilty of misbehaviour with the girl students and recommended their expulsion. But the Vice-Chancellor did not accept that recommendation and those very students are the main body guards of the Vice Chancellor. When such incidents are taken place how discipline can be maintained there ? There can not be any discipline, when the Vice Chancellor shields such anti-social elements.

A murder was committed in the University Campus, But the Vice Chancellor did not cooperate with the Police to bring the guilty to book. On the other hand he shielded the guilty. Now how students can remain calm there when the Vice Chancellor is acting in a partisan way ?

It is sad that even a genuine demand of the Students Union regarding hostel accommodation was not accepted. The Union had suggested that if Rewa Bharan was turned into a hostel, it could provide accommodation for 200 students. The authorities on the other hand handed over that building to the American Institute. This is a very bad state of affairs.

The question is that there should be no favourtism. One section of the students wants to hold R.S S Shakha there and they have been permitted to do so. But there is no freedom for other section of the students. If it is not favourtism, then what it should be called ? Does the hon. Education Minister consider it proper in a democracy and in a secular state ? In view of all this I suggest that a high Powered Commission should be appointed to enquire into the affairs of the Banaras Hindu University and that Commission should be appointed by the visitor who is no less a person than the President himself.

The temple of learning has been converted into a police camp and the elected representatives are being turned out one by one from the University. The Education Minister treated them sympathically when he was a Vice-Chancellor of that University and the situation was improved considerably.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The discussion which is going on regarding the prevailing unrest among the students is a serious one. It was a great dream of Mahamana Malviyaji to build an ideal University and the students belonging to this institution would be of great reputation and will spread. Indain culture abroad I regret to say that lawlessness, arson and other kinds of mischiefs are prevailing in the campus of the University.

Great educationists like Dr. Radha Krishan, Dr. Joshi and Dr. Trigun Sen had served the University, as Vice-Chancellor. Dr. Joshi is a learned man of repute he is not connected with any political party. He wants that education may spread there. But I may say it clearly that the University has become an arena of political parties like Jan Sangh, Communists, Praja Socialists and various other parties. Regarding the incidents, which took place there, I may state that four students were expelled from the University, as a result of this, the other students became agitated. The proctor was gheroed and may other teachers were badly beaten. The politics has a clear hand in all these incidents.

The flame of this agitation is not limited to Banaras University only, it has spread to Allahabad, Lucknow and Agra also. The anti-social elements are taking advantage of these situations. It is high time that peace should be restored in Kashi University. There the agitation has been going on for the last one month and it is now turning to violence. What steps the Education Minister has taken in this respect. It is his duty to get the agitation ended immediately so that peace may prevail there.

I think that unless there is co-ordination between three impout out bodies namely management committee, students and teachers. There cannot be smooth functioning in the University. The Hon. Minister may look into it so that these bodies may work in the spirit of co-operation for the welfare of the institution.

In the end, I may urge that the students, who are in jails, should be released without further delay. As the unrest among students is a national problem so a committee on national level be appointed which may look into its causes and give remedial measures. The teachers of primary and secondary schools are on agitational path and many of them are in Jail. It is requested that the Hon. Minister may get them released so that peaceful atmosphere may prevail there.

Shri Satya Narayan Sinha (Varanasi) : I want to state some facts regarding the happenings which are taking Place in Hindu University. I will ask my friends to see the real causes behind all these things. Is it not correct that four girls were gheraoed at the time of convocation ? Their four students raped a girl in Birla Hostel but attempts were made to cover up all these incidents. A muslim boy was murdered for nothing by a group of students but no enquiry has been conducted so far.

At the time of Union's election, candidate was given a ticket illegally but he was defeated and with the result the trouble started there. When a deputation of students came to the Education Minister and the President to convey their greivances then the Vice-Chancellor took action against them. When they raised their voice against their expulsion from University as also against the maipractices and corruption, they were kicked away and the culprits were given undue protection. When we asked why action was not taken

againts those anti-social elements who were creating trouble ? The hon. Minister stated that he had not taken action against then since they as well as their relatives had regretted for their action. The S. S. P. came in between and assured the students that they would anyhow get the dispute settled. But later on they said that the Vice-Chancellor was not prepared to fulfill any of his assurances. This passed the way for another agitation. The Vice-Chancellor then called the students at his bungalow and where they were given severe beatings. The police did not beat them. They were beaten by goondas and later on handed over to the police. On student lost his one eye and the other passed blood in his urine. None of them could get up even. Is not a fact that as many as twenty students are lying in the hospital ?

This is what happened at the Vice-Chancellor's bungalow. Where students were called and beaten by the unsocial elements. Whole of the city and even the State, is agitated over it.

I, therefore, demand that due forsightedness should be shown to control these incidents and a committee should be appointed to hold an impartial inquiry into the incidents which took palce in the Banaras Hindu University.

Shri Sita Ram Kesri (Katihar) : You should permit those persons to speak first who know about this matter and who have given you their names for this debate.

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही चलेंगे ।

Shri Shashi Bhushan (Pupri) : The issue relating to the Banaras Hindu University can be settled only when there is a shift in our educational system. First of all I would say that no educational institution should be named after a community or a centre. All such names should be changed forthwith otherwise we will be endangering the fortunes of our leaders which might come out of these institutions.

We are all ashamed of to hear what happened in the Banaras Hindu University. A function was held there on account of Raksha Bandhan, but when the girls reached there they were raped by some students. The student's court then expelled those students who raped the girls. But students of the student's-court itself were severely beaten and imprisoned in the University whereas the culprits were taken back. It is highly objectionable, and it should certainly be inquired into.

The Vice-Chancellor Mr. Joshi is no doubt an impartial man but it is also a fact that he indulged in encouraging one party at one time and the other later on. It does not behave a Vice-Chancellor. Religion and politics should always be kept away from education. It it really a matter of sorrow that a Muslim student was killed. After all he too was a human being. But this all happens because our educational institutions have been named after religion cast or community e. g. Jat College in Rohtak, Gaur Brahman School, Vaish College etc. Therefore, a national institute should be set up to name all the educational institutions on a national-bias.

श्री श्रीधरन (बडागरा) : शिक्षा प्रणाली के दौर में आये इस नाजुक समय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा उस समय हो रही है जबकि सारे देश में विद्यार्थियों की उत्तेजना देश में एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुकी है । विद्यार्थियों का असन्तोष केवल बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि सारे देश में यह फैल चुका है । देश के अनेक स्थानों पर हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं । मैं इन घटनाओं की निन्दा करता हूं परन्तु प्रश्न

यह है कि ऐसी घटनायें आखिर होती ही क्यों हैं ? इसका कारण यह है कि शिक्षा मन्त्री का ध्यान शिक्षा सम्बन्धी इन समस्याओं का समाधान करने की ओर नहीं है ।

किसी भी देश में, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में विद्यार्थी ही प्रत्येक प्रगतिशील आन्दोलनों के नेता और अग्रगामी होते हैं । विद्यार्थियों के मध्य इस अनुशासनहीनता का कारण यही है कि हमारे विश्वविद्यालयों में निराशाप्रद वातावरण है तथा हमारी अर्थव्यवस्था के कारण हमारे घरों में क्षुब्धता की गहरी भावना विद्यमान है । सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है ।

एक महान् विचारक का कहना है कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा वर्णमाला पढ़ाना क्रान्ति के उद्घाटन के समान है । परन्तु हमारे स्कूलों की स्थिति क्या है । समाजवादी आन्दोलन में भाग लेने वाले हम लोग सदा ही पृथकीकृत स्कूलों के बन्द किये जाने के मांग करते रहे है तथा इस बात की मांग भी करते रहे हैं कि धनी व्यक्तियों के बच्चों को विशेष स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने की छूट नहीं होनी चाहिये । विश्लेषण से पता चले गये कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बेटे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, यह हमारे समाज में परम्परागत व्यवस्था बन गई है तथा आज छात्र इसके विरूद्ध विद्रोह कर रहे हैं ।

शिक्षा आयोग ने सरकार को सिफारिश की है कि सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय प्रयत्न करने की तुलना में हमारी शिक्षा प्रणाली के कई पहलू विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं । इस परिस्थिति के लिये जिम्मेवार कौन हैं । मैं इसके लिये सरकार को जिम्मेवार ठहराता हूँ । सरकार का अनिश्चित तथा ढुलमुल रवैया इसके लिये उत्तरदायी है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार की शिक्षा नीति कभी एक रूप नहीं रही जिससे सभी छात्रों में अशान्ति तथा अव्यवस्था है ।

मैं एक और बात की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई मूल मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया है । दक्षिण में भाषा समस्या के कारण छात्रों में अभी तक उत्तेजना है । मालूम नहीं कि आकाशवाणी से अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचारों के प्रसारण का समय क्यों बदल दिया गया है । हमारी शिक्षा संस्थायें जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता से मुक्त की जानी हैं । बनारस विश्वविद्यालय की घटनायें जातीय तथा साम्प्रदायिक विवादों के कारण घटी हैं । मैं शिक्षा मन्त्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बात को समझें कि यह समस्या एक महत्वपूर्ण नहीं है । छात्र समाज का आइना हैं, जब वे विद्रोह करते हैं तो सामाजिक ढ़ांचा गिर जाता है, छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

Shri Sita Ram Kesri : Mr. Deputy Speaker, Sir, the students of Banaras Hindu University have played a major role in our struggle for freedom. This University is a fountain of national ideology. Such an institution should not be made an area for political rivalry.

Not only in this country but also throughout the world an agitation is going on amongst the student. One of the reasons of discontentment amongst the students is uncertainty about their future. Another reason is the discontment amongst the teachers

because of low pay scales. The Government should remove their discontment by improving their pay-scales.

I request the hon. Minister of Education to see that no political party, whichsoever it may be, should be allowed access to the University and particularly Banaras Hindu University. Members of Parliament having independent views should be sent in the University to set up normalcy.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The situation now prevailing in the Banaras Hindu University is a consequence of resentment amongst the students. I fully endorse the demand made in the House that the President, who is also visitor of the University should immediately appoint a committee to go in to the this question. The Minister of Education should also advise the President should constitute such a committee.

It is not proper to suggest that the students should not participate in politics. A demand is being made that all the persons above 18 years of age should be given the right of franchise. Such a right has already been given in a number of European countries. The youth have to build the future of the country. They should, therefore, understand politics.

The students have to face the problem of unemployment after education. I would like to know steps taken by Government to provide them with jobs.

Those students, who have been arrested, should be released. Attempts should be made to remove the feeling of discontment amongst the youth. Their future is uncertain. The Government is doing nothing to remove unemployment amongst educated persons.

Our social structure is not properly organised. The students should make endeavours to remove social inequalities and support the efforts for establishing an equitable social structure.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, whenever there is a discussion on student agitations or disturbances, the intellectuals and particularly the educationists give arguments for their defence. It is said that such things are happening throughout the globe and not in India alone. I would, however, like to tell the Education Minister that India has her own traditions and we cannot overlook indiscipline amongst our students on the pretext of such things being a part of world wide agitations.

I appeal to different political parties and the party in power to consider the question of deteriorating condition in educational institution by rising above the party levels Political leaders belonging to different parties and having interest in education should sit with educationists and try to find a solution to this problem. Banaras Hindu University has become a centre of political activities. The recent happenings in the University are unprecedented in history. Never before such violent activities took place there. We should go to the root of the matter and see whether there is any conspiracy to use the immature students for certain gains.

There are certain professional students in the Banaras Hindu University. They continue in the University for 8 to 10 years and they are paid for the same. The Minister should consider this question.

The Government should treat all the Universities equally. It had been decided that all the colleges in Varansi should be affiliated to Banaras Hindu University. A similar decision should also be taken in the matter of Aligarh Muslim university.

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रो० अमीन ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने अनिश्चितता से काम लिया हैं तथा मुझ में स्वायतता की भावना के बारे में भ्रम है। जब हाल ही में विश्वविद्यालय में उपद्रव हुए थे तो दोनों सदनों में सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि विजिटर को विश्वविद्यालय में स्थायी उथल पुथल की स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इस समस्या के समाधान के लिये सुझाव दे। मैं समझता हूं कि उपकुलपति तथा सम्बन्धित अध्यापकों का कर्त्तव्य है कि छात्रों से मिलें। यही कारण है कि मैंने ही हस्तक्षेप किया और न ही विजीटर को हस्तक्षेप करने की सलाह दी है।

मैंने उप कुलपति तथा विद्यार्थियों से कहा था कि इन समस्याओं को मिल बैठ कर हल करें। मैं नहीं चाहता की बाह्य तत्व विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करें।

यहां पर कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति में जनता को भरोसा नहीं होगा। मैंने बताया था कि समिति के सदस्यों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा मन्त्रालय की सलाह से किया जायेगा। मैंने यह आश्वासन उपकुलपति के कहने के अनुसार दिया था। गत मास की 16 तारीख को कार्यकारी परिषद की बैठक हुई और उपकुलपति ने यह बात वहां नहीं रखी और कार्यकारी परिषद् ने समिति नियुक्त कर दी। जब उपकुलपति यहां आये तो मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगे कि इस मामले को कार्यकारी परिषद के समक्ष फिर से रखा जायेगा। आज वह बैठक होने वाली है। इस कारण यह विलम्ब हुआ है। मुझे अध्यापकों के संघ से पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा है कि वे उपकुलपति के शान्ति स्थापना सम्बन्धी प्रयत्नों में सहायता कर रहे हैं। इस में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका आभास बाद की घटनाओं से होता है ?

श्री बलराज मधोक : मैं जानना चाहता हूं क्या गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी और ठीक परिस्थितियां स्थापित करने के बाद ही समिति नियुक्त की जायेगी ;

डा० त्रिगुण सेन : कुछ घटनाएं गत पांच छः महीनों से हो रही हैं। विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता की कुछ घटनाएं भी हुई है। उपकुलपति का सुझाव था कि एक समिति नियुक्त की जाये। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० जोशी एक साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं हैं। मैं नहीं मानता कि वह राष्ट्री यस्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हाल की घटनाओं में जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का आदेश दिया है। यदि किसी विद्यार्थी ने अनुशासन तोड़ा हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपकुलपति का दायित्व है और उसके अधिकार भी है।

श्री बलराज मधोक : क्या आप यह आश्वासन देंगे कि जिस किसी ने भी गड़बड़ की है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उमानाथ : मन्त्री महोदय को यह गारन्टी देनी चाहिये कि जांच के समय में उप कुलपति विद्यार्थियों को तंग नहीं करेंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : सदन इस बात से मेरे से सहमत होगा कि यदि किसी विद्यार्थी ने हिंसा को ही तो उसके साथ सामान्य नागरिक का सा बरताव होना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने स्थिति को बहुत खराब रूप में बताया है। ऐसी कोई बात नही है। हां कुछ घटनाएं अवश्य हुई है। श्री मधोक तथा श्री बरुआ ने कुछ सुझाव दिये है, उन पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा। शिक्षा आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति में सरकार के साथ अन्य लोगों को भी सहयोग देना है। इस बारे में सरकार जो कार्यवाही कर रही है, उस बारे में मैं ब्यौरेवार बताऊंगा।

विद्यार्थियों में अशान्ति के समाधान हेतु बहुत से सुझाव दिये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में एक समिति बनायी थी। डा० सेन इसके अध्यक्ष थे। इस समिति ने दो वर्षो तक देश का दौरा किया। उनकी मुख्य सिफारिश थी कि विद्यार्थियों में अपना शिक्षा संस्था के प्रति लगन तथा श्रद्धा की भावना उत्पन्न की जानी चाहिये। मैंने इस सिफारिश पर अमल किया था और उस समय बनारस में अशान्ति नहीं थी। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का कर्त्तव्य है कि अपने विद्यार्थियों में अनुशासन के प्रति लगन बढ़ाये। एक वातावरण बनाया जाना चाहिये। श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा है कि एक राष्ट्रीय समिति गठित की जानी चाहिये। वह समिति अशान्ति के कारणों का पता लगाये। ऐसी बात नहीं। हमें कारण मालूम हैं। अब प्रश्न तो हल ढूंढने का है। इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : DEMANDS OF TEACHERS OF HIGHER SECONDARY SCHOOLS IN U. P.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is a matter of coincidence that we are discussing the matter concerning teachers immediately after the matters concerning students. It is in India that education is given almost the lowest priority, so far the Government expenditure is concerned. In U.P. the plight of teachers is all the more miserable. The former Education Minister Shri Shrimati had admitted this. It is very unfortunate that having known this, no action has been taken to ameliorate the lot of teachers. The teachers on there part did not take any drastic action. Their agitation was peaceful. They were forced to take recourse to agitation as a last resort. If teachers take this step, its effect on students can be well imagined. It is due to this that students unrest is also spreading.

Their demands are very small. Firstly they want that their salary should be paid directly by Government. as is done in Kerala and Mysore. Their second demand is that the pay and allowances of teachers of private schools should be brought at par with that of teachers of Government schools. The third demand is that the recommendations of Kothari Commission should be implemented at once. The conditions of non-teaching staff should be improved and fifthly they should be paid salary in time and previous arears should be paid without delay.

These are their demands.

{ श्री गादिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

According to Government statistics and as-per the information collected at the time of Charan Singh Ministry, it will not put any additional burden, if salary of teachers is paid directly by Government to the teachers of private schools. It will rather result in net saving of Rs. 2 crores. I am not aware whether information in this regard has been received by Government or not ? I feel Government should concede this demand without any hesitation.

The demand regarding equal pay was accepted by the Government headed by Shri Charan Singh and an announcement was made to this on 7th August, 1967 in Upper House of State Legislature. The Governor must honour the decision of that Government. I had raised this issue at the Consultative Committee of M.P.'s meeting at Nainital. I was told there that they were getting almost equal emoluments. I cannot understand as to why then these teachers are agitating ?

Government had appointed the Kothari Commission. Lakhs of rupees were spent on it. What is the use of appointing such commissions, if their reports are not to be implemented ? It is the duty of Government to implement the recommendations of the Commission.

The scale of pay of J.T.C. teachers in Uttar Pradesh is Rs. 104-182 whereas the pay of a peon starts from Rs. 111/-. Even if a J.T.C. teacher passes M.A. his pay will not increase.

So far as the question of clerks working in schools is concerned, you will be sorry to know that the Rules of Services for them have not been prepared for them till 1968. They are getting Rs. 50 as salary and inspite of that they have to depend upon the principal, Manager and the secretary of the School. The condition of class IV employees is even worse. The Government should prepare rules and regulations for the services of Class III and IV employees. The Government should not issue ordinance against the teachers. It should be issued at proper time otherwise it will lose its importance.

The Primary teachers in the Municipal Schools of Uttar Pradesh are getting only Rs. 80 per month. Every State is supposed to spend 20 percent of its income on education and out of that 10 percent of the income is supposed to be spent on education according to the recommendations of Kher Commission. The Government is only spending 6 percent on education. Therefore the Central Government should give 21 crores to Uttar Pradesh for the poor teachers. There is a lot of difference between the standard of schools in the country. The socialistic pattern of society should start from here.

The main reason behind falling the standard of education in Uttar Pradesh is the dissatisfaction amongs the teachers. The agitation of teachers at Present is free from politics but I fear if their demands have been neglected like this they will resort to politics. It will a dangerous state for the country. Every efforts should be made to find out ways and means to solve the problem of teachers in Uttar Pradesh.

The Government should prepare such a Scheme that the teachers of Uttar Pradesh may not resort to strike and they may be paid like the teachers of the States of Punjab, Haryana and they may be able to fed their family.

Shri Shiv Narain (Basti) : If ten percent of the total Budget allotted for Uttar Pradesh had been spent on education, this situation would have not arised. The managing committees of education are worst. The education in India should be nationalised. I appeal that the teachers should remain away from politics. The demand of the teachers are proper and the figures given by the Government are not correct. The teachers should be given well treatment. They should not be sent to jails. All their demands are proper and they should be met. I hope that the Hon. Minister will accept their demands and all the teachers will be released.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जेलोर) : वर्तमान अभियान का मुख्य कारण देश में समान शिक्षा प्रणाली का न होना है। देश में अध्यापकों की नियुक्ति के नियम और वेतमान भिन्न-भिन्न है। इसी के परिणामस्वरूप वर्तमान अभियान सामने आया है। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया था कि अभियान अनुशासनिक तरीके से किया जाना चाहिये। लेकिन इसके लिये दोनों का सहयोग आवश्यक है।

ये अभियान 20 वर्ष पूर्व आरम्भ क्यों नहीं हो गये। इसका मुख्य कारण यह है कि अब शिक्षा प्रणाली में कुछ त्रुटियां है जो पहले नहीं थीं। उन्होंने पहले विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदनों का सहारा लिये लेकिन जब उनसे काम न चला तो उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर इस हथियार का सहारा लेना पड़ा। कोई भी भारतीय इतने कम वेतन में गुजारा नहीं कर सकता।

देश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आने की शिकायत की जाती है। अध्यापकों में इस प्रकार का असंतोष रखकर हम कैसे अच्छे स्तर की आशा कर सकते हैं।

शिक्षकों की मांग को पूरा न करने के लिये धनराशि की कमी की दलील दी गई है। हम करोड़ों रुपया प्रशासन कार्यों पर व्यय कर रहे हैं। हमारे पास बोकारो इस्पात कारखाने को स्थापित करने के लिये धनराशि है लेकिन हमारे पास शिक्षकों के वेतन स्तर सुधारने के लिये धनराशि नहीं है। अतः यह दलील उचित प्रतीत नहीं होती। यदि देश का विकास करना है तो देश की इन मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि हमें शिक्षा प्रणाली में अनुशासन लाना है तो हमें न केवल कोठारी आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना होगा बल्कि उनके लिये इससे भी अधिक कार्य करना होगा।

हमें शिक्षा प्रणाली में भी अच्छी क्षमता को बनाये रखना है। यदि हम ऐसा करने में समर्थ नहीं होते तो आयोग के प्रतिवेदन बेकार हो जाते हैं। यदि आप आयोग की सिफारिशों

को क्रियान्वित नहीं करते तो आप आयोगों की नियुक्ति पर फिजूल खर्ची मत करिये। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वे शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करें।

डा० त्रिगुण सेन द्वारा की गई कार्यवाही की मैं सराहना करता हूं। इससे देश में समान शिक्षा प्रणाली स्थापित होगी। यह दुःख की बात है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय घटा दिये जाने की संभावना है। देश में शिक्षा को उचित महत्व दिया जाना चाहिये। यदि शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय में कमी की गई तो शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। समाज के स्तर में भी गिरावट आ जायेगी।

सरकार को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये कि वे शिक्षकों और सरकार के बीच स्वतन्त्रतापूर्वक विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उन्हें परेशान न किया जाने का आश्वासन दिया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति का शासन है अतः स्थानीय प्राधिकार पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को समस्या को हल करने के लिये बिना विलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिये।

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : It is a matter of great concern that our teachers who are shouldering the responsibility of making future of our younger generation, have to adopt the method of strike. In order to avert this strike, I would request the Government to give an assurance to the effect that they will accept their reasonable demands. The Education Minister has himself admitted that the economic condition of the teachers of Uttar Pradesh is miserable and therefore Government cannot overlook the injustice being done to them for long.

I have a copy of Government order dated 15 November, 1967 in which it was agreed that the teachers of Aided Higher Secondary School and Junior High Schools will be paid dearness allowance at the same rate on which it is being given to the teachers of State Educational Institutions. But it has been stated in the Rajya Sabha that Government have not given any assurance to this effect. I would like to have clarification from the Education Minister.

The Central Government had given Rs. 48 lakhs to the U. P. Government with a view to give assistance to the teachers to the State. I want to know the manner in which that amount was disposed of. In case Government is unable to take concrete steps in the matter, Education may be brought under the concurrent list. Government should give equal pay for equal work.

In many cases teachers do not get salary in time. We have received many complaints about such delays. Government should remove all such irregularities which cause delay in payment of salary to the school teachers for months together. They should formulate a scheme to improve teachers' lot. Seperate allocations should be made for the regions in which the recommendations of Kothari Commission could not be implemented so that imbalance is removed.

I would also request the teachers not to give political colour to their agitation. It will affect the future of children.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : यह खेद की बात है कि हमारे बच्चों के भविष्य निर्माता जेलों में बन्द हैं। हमें आशा थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की

मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। हम कई बार प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में मिल चुके हैं परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यदि महानिषेध लागू करने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकती है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के वेतनों को समान स्तर पर लाने के लिये एक या दो करोड़ रुपये की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ?

अन्य वर्गों की अपेक्षा शिक्षकों के वेतन बहुत कम हैं। प्रति वर्ष केवल कुछ अध्यापकों को पुरस्कार देने से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हमारे देश में वेतन में अन्तर का अनुपात 1 : 100 है। शिक्षक वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थान देने के लिये हमें उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही होगा।

यह संतोष की बात है कि इस वर्ग ने अपने आपको संगठित किया है और अपने अधिकारों तथा शक्ति को महसूस किया है। उनकी मांगें न्यायसंगत हैं और यदि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो हमारे देश का भविष्य भी अन्धकारमय होगा।

कोठारी आयोग ने सिफारिश की है कि अन्तरिम सहायता के रूप में उन्हें तत्काल 100 रुपये दिये जाने चाहिये। सरकार ने इसे भी क्रियान्वित नहीं किया। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में, जिनका वेतन सबसे कम माना जाता है, शिक्षा मंत्री को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि उनकी स्थिति सुधारने के लिये वह क्या कर रहे हैं ? सरकार को इस सम्बन्ध में धन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। एशिया में शिक्षा पर हमारा प्रति व्यक्ति खर्च सबसे कम है। यदि सरकार यह चाहती है कि देश में लोकतन्त्र कायम रहे तो उन्हें समाज को शिक्षित बनाना चाहिये। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब भी 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। यदि सरकार ने शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था नहीं की और शिक्षकों को उचित वेतन नहीं दिये तो देश का भविष्य अन्धकारमय होगा। सरकार को प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को उपयुक्त वेतन देने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। इन अध्यापकों को तुरन्त रिहा कर देना चाहिये और इस प्रकार अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : There cannot be two opinions about the fact that teachers have a very important place in the society. The future of the country depends on the teachers. But if the teachers do not get sufficient pay to make their both ends meet it will not be possible for them to prepare foundation of the younger generation. The teachers are getting less than even peons and constables. Moreover there is disparity in the pay-scales of teacher in different States. This is great injustice.

Instead of teaching discipline to the students we make them cramme books. We are not making them aware of their responsibilities.

I will not hesitate in saying that Government pays attention to the demands of the people only when they resort to strike. Government should give ear to the demands of the people if they are put in the proper manner before the Government. People resort to strikes and agitations because they are compelled to do so. The responsible officials of the Government do not allow the people to see the ministers for redressing of their grievances. Government should also deal the people with strong hand who resort to booliganism without any reason.

I shall conclude with the following suggestions.

(1) Recommendations of all the commissions including the Kothari Commissin set for the consideration of the pay scale of teachers should be accepted and implemented.

(2) Salaries of all the teachers in the contiguous States such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh should be the similar to each other.

(3) Some standard of education should also be fixed if any teacher shows good results he should be given higher salary as an incentive. I would also suggest that any class shows results less than fifty percent the annual increments of the teacher concerned should be stopped.

(4) Services of the top educationists in the country should be sought for the training of the teachers, which may teach nationalism, discipline and make them aware of their responsibilities towards the nation and children.

(5) The Government of India should grant to the teachers of Himachal Pradesh the pay scale recommended by the Kothari Commission. Necessary financial help should be given to the Himachal Pradesh Government, if sought.

Mr. Chairman, problems of the teachers should be considered seriously and sympathetically so that they could perform their duties towards the children faithfully. I appeal to the Government to consider sympa thetically the demands of the teachers and those who are in jail should be released.

Shri Narain Swarup Sharma (Domariganj) : It would have been better had the Prime Minister remained in her seat for some time more,

The teachers for whom we should have been proud of one being put into jails in Uttar Pradesh now-a-days. The teachers are kept in the Central jail, Luknow, where ordinary criminals are kept. Fifteen teachers including the 87 teachers alongwith five babies are imprisoned in the Meerut jail which is only 40 miles from here.

I have received a chit from the Secondary Teachers Union wherein it has been stated that a peon gets rupees 105 as compared to a untrained graduates salary of rupees 85 only. If that it so then it is an explosive situation which should be tackled on emergency basis.

At present the problem is not only of less salary but also that this salary is not paid to them in time by the Managing Committees concerned. Salary worth 11 lakhs of rupees is still to be paid in the Balia district alone. In some districts teachers have not received their salaries for the last one or two years. In these circumstances I will suggest that salaries of the teachers should be paid from the government treasury. If Government 80 percent of the fees and Central grant in his own hand two and a half crores of rupees can be saved. A scheme to this effect was accepted by the education minister of the defunct United Front Government. I also gave this suggestion in the meeting of the U. P. Advisory Committee at Nainital.

Now it is said that United Front Government did not accept the demands of the teachers and that these teachers can now only be considered by the popular Government. But I would like to state that recommendations of the Kothari Commission have been accepted in Punjab and Bihar although there is no popular Government in those States. I would, therefore, request that these recommendations may be accepted and implemented in Uttar Pradesh also.

So far as payment from the government treasury is concerned, such provision has already been made in Kerala and Mysore. So there should be no difficulty in introducing this system in Uttar Pradesh

I think that the Government is still in a position to spend more money on education. Priorities should be reallocated.

A committee consists of the representatives of the Government and teachers on the basis of Burnba Committee of England should be appointed to go into the matter of pay-scale the teacher. Decisions of this Committee should be accepted and implemented.

Nine thousand teachers who are at present in the jail should be released and their demands be accepted.

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : It is very unfortunate that teachers all over Uttar Pradesh are in strike since 2nd December. There has been great unrest amongst the teachers of all categories for the last few years.

The condition of the teachers of primary and secondary teachers in Uttar Pradesh is pitiable as compared to the condition of the teachers of other States. They are demanding that discrimination amongst the pay-scales of the teachers of Government and non-government schools and also difference in the dearness allowance should be done away with. This demand is justified and it has been accepted in principle. Their second demand is this that payment of their salaries should be made from the government treasury. The reason for this demand is that the non-government schools have become the business centre in Uttar Pradesh. The teachers are not paid the salaries for which they are appointed. They are paid less salary and are forced to sign for full salary. That is the position in that State. So, their demand for payment from government treasury is also justified and it should be accepted.

About 90 percent teachers are on strike in Uttar Pradesh. Some solution should be found out of their problems. Education system in the State is completely paralysed. Thousands of teachers have been put in the jails. I do not want to held the Central Government responsible for this unfortunate condition but I would not hesitate in saying that the government which run the State during the last twenty years is responsible for all this. That government fail together the necessary resources and also fail to accept the reasonable demands of the teachers. The Union education minister is expressing his concern over the situation but he is also saying that it is a state subject and Central cannot interfere in it. In this connection I would say that we can reconsider this matter and a round table conference can be called and if found necessary, an amendment can be carried out in the Constitution. But we should not play with the future of the youngsters.

So far as the question of payment to teachers from the government treasury is concerned, I do not accept the figures put forward by the Government. I do not think that there will mean extra burden on the Government to the tune of one crore of rupees. But one thing is clear that teachers will be saved from the hardships of the managment of the schools. The teachers will get their full salary.

If the recommendations of the Kothari Commission are accepted and pay scales of teachers of government and non-government schools are brought at par there will be an additional burden on the government to the tune of three or four crores. But I would say that this is a burden which should be borne. It will satisfy the teachers and there will be vest improvement in the field of education.

I appeal to the Prime Minister and the education Minister to release the teachers immediately who are jail. The Government of India should take the initiative and discuss this matter with the representatives of the teachers. The situation should not be allowed to deteriorate further. Their demands are just and there should be accepted.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I congratulate the leaders of the Uttar Pradesh Secondary teachers Union for violating the ordinance of the Governor of Uttar Pradesh and resorting to successful strike.

Eight thousand teachers have been put in the jail and daily seven rupees per head are being spent on them. It costs about 56,000 rupees per-day to the Uttar Pradesh Government. But they are not prepared to accept the recommendations of the Kothari Commission neither they are prepared to bring parity in the dearness allowance.

This problem is not going to be solved if it is left to the Governor of the state. The teachers have requested the Prime Minister and Union Education Minister to intervene in this matter.

The United Front Government gave some assurances to the teachers but these have not been translated into action. All the Government employees except the teachers were granted dearness allowance in August.

There are about 56,000 secondary teachers in Uttar Pradesh. Out of these about eight thousand are in jail. About 99 percent teachers are on strike. If the Government considers that they will be able to suppress the strike by putting the teachers in jail then I would say that Government is on the wrong foot. This strike and agitation will continue till all the 56,000 teachers are put in jail.

The Government should not have any difficulty in accepting the demand of the teachers in regard to their payment from the treasury. As Shri Shastri has stated Government will save 2,62 lakh rupees in this way.

It has also been said that extra six crores are needed to meet their demands. But the teachers have clearly stated that 2,05 lakh rupees will serve their purpose. The Government is in a position to bear this burden.

I would request the Government to grant parity so far as dearness allowance is concerned. Necessary amount should be granted to the State Government for the purpose. I would also request the Union Education Minister to declare that imprisoned teachers will be released and that the Central Government will give the necessary money to bring parity in the dearness allowance.

Shri Ram sewak Yadav (Barabanki) ; The ill-treatment being meted out to the primary and secondary teachers in Uttar Pradesh is not comparable with the teachers anywhere in the world

Members from all corners of the House have supported the demands of the teachers. I would say that if the hon. Minister wants to react an any solution be should first of release the teachers who have been put in the jail. Eight thousand teachers have been arrested. It is the biggest number of arrests during the last five or six years. The pay of scales of the teacher in Uttar Pradesh is very low. It is said that there is no funds for raising their pay scales. But a large sum of money is being wasted on useless things in Uttar Pradesh. According to Kothari Commission the lowest paid employees in

the country are the middle school teachers. Inspite of this the salaries of some of teachers remain outstanding for three or four months and sometime even for an year.

The Central Government should provide the necessary assistance to Uttar Pradesh. It should not wait for the contribution of the State.

Kothari Commission has recommended that the difference between the salary of the primary, middle and University teachers should be in the proportion of 1 : 2 and 3. Politics should not be brought in this matter. The demands of the teachers should be fulfilled. The Hon Minister should give some assurance in this regard and he should try to find out some solution of this problem.

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : It was the Congress Government who gave maximum facilities to the teachers and who the best for improving the conditions of the teachers. Their salaries and dearness allowances were also raised by the Congress Government.

The Managing Committee in Uttar Pardesh has been formulated in the interest of teachers. But it is not possible for this Committee to stop indiscipline. It is true that the condition of the teachers in Uttar Pradesh is pitiable. It is not possible for them to make even two ends meals. They have to depend on loans. We have full sympathy with them.

We are trying to find out a solution of this problem.

The conditions of the teachers should be improved and their demands should be met. The Central Government should also give assistance in the matter. Uttar Pradesh Government should also try to obtain as much assistance as possible from other sources also.

I fully support the demands of the teachers of Uttar Pradesh. But some practical attitude should be taken in this regard. Merely agitations and going the jails will not solve the problem.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) आज समस्त देश के शिक्षक, विशेषकर निम्न वर्ग के शिक्षकों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

सरकार की समस्याएं पैदा करने की नीति रही है । उसने छात्रों को निराश कर उनकी समस्या खड़ी की । उसने अध्यादेश जारी कर अराजपत्रित कर्मचारियों की समस्या खड़ी करी। उसने शिक्षकों की भी समस्या खड़ी करी । देश में कब तक हड़तालों और लोगों को जेल भेजने का सिलसिला जारी रहेगा ।

शिक्षकों के साथ सदन के सब वर्गों को सहानुभूति है । उन्होंने अपना प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से किया है ।

प्रधान मन्त्री और शिक्षा मन्त्री को देश में शान्ति स्थापित करनी चाहिये ।

शिक्षक वर्ग देश का सबसे निर्धन वर्ग है । उनका वेतन केवल 84 रुपयों से आरम्भ होता है । इतने कम वेतन में वे कैसे गुजारा कर सकते है । परिवार नियोजन पर खर्च किये

जाने वाली 211 करोड़ रुपये की राशि में से यदि केवल 2 करोड़ रुपये को भी शिक्षा पर खर्च कर दिया जाये तो इस समस्या को किसी सीमा तक हल किया जा सकता है। सरकार को बन्दी बनाये गये सब शिक्षकों को शीघ्र छोड़ देना चाहिये ।

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : I fully support the demands of the teachers. All the sections of the House have supported the demands of the teachers. Their demands have already been getting the sympathy from all sections of the people in Uttar Pradesh In such circumstances you have a great responsibility whether to fulfil or not to fulfil all their demands. I hope that you will take such an action that the condition of the teachers may not further deteriorate in Uttar Pardesh.

Shri Shinkre (Panjim) : I know the difficulties of the teachers very well because I had been a teacher for 11 years. The strike in Goa was held because the teachers of Khaggi areas were not taken in the Government schools. After that an institution named 'Gomantak' was established in Goa which recommended that because Marathi is the language of the State so Goa should be merged with Maharashtra. The teachers and the students should not enter politics. But they have to do it under compulsion. The teachers have a big power behind them. Therefore, I wish that the Government should pay attention towards solving their problems.

The prohibition can only be implemented throug education. There is no need to established a separate Ministry for it. The amount saved in this way may be used on education for the welfare of teachers and for educational institutions.

Shri Bibhuti Mishra (Motihar): The demands of the teachers of Uttar Pradesh should be met as early as possible.

The teachers now-a-days are not taking interest in teaching. I also want that their appropriate demads should be met and their suspension should be stopped. The Government should take appropriate action in this matter. Government can spend some money for the benefit of the teachers. Teachers are the nation builders.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat jha Azad) : I agree that the scales of pay of the teachers of Uttar Pradesh are the lowest in the country. An increase in the pay scales of the teachers in Haryana. Bihar Government has accepted in principale the scales of pay suggested by the kothari Commission and it will be implemented soon.

We have full sympathy with teachers and we are very well aware with regard to their demands. So far as the question of payment of salaries to the teachers is concerned, it is true that there are certain institutions who are not paying salaries to teachers.

Instructions in this regard has been issued to pay to the teachers out of the grant given to those institutions (interruptions).

The teachers have also been paid the dearness allowance in August, 1967 like Government employees. But the dearness allowance raised for Government employees in August, 1968, has not been paid to teachers.

The Government want that uniform scales of pay may be implemented in all the States of the country. If Rs. 150/- are paid to every teacher in Uttar Pradesh, it will require enough funds. It requires 676 lakhs of rupees to fulfil all the demands of

the teachers. Additional resources will be required for fulfilling their demands President's rule cannot compel a State Government to spend such a huge amount which may be a sort of securrent expenditure we cannot spend such a huge amount for such a small period.

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : Taking into consideration the difficulties of the teachers in Uttar Pardesh, the Central should provide assistance to the tune of 50% percent to the State

Shri Bhagwat Jha Azad : So far as the question of co-ordination of higher education is concerned, the Central Government bas been paying 80 percent for five years for university teachers. It is not possible for the Government to pay for the primary and middle education for all the States in the country states should find out their own resources.

We have asked the State Government to fulfil some appropriate demands of the teachers. we want that the teachers of Uttar Pradesh should call off their strike. It is very said that some teachers have been sent to jails. This prcblem cannot be solved unless a discussion is made between the representatives of teachers and the Government. An atmosphere for that should be created in the country.

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार 16 दिसम्बर, 1968/25 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok-Sabha thenadj ourned till 11 of the clock on Monday the 16th December, 196 8/Agrahayana 25, 1890 (Saka)